[2025] 9 एस.सी.आर. 194: 2025 आईएनएस 979

कर्नाटक राज्य

बनाम

श्री दर्शन इत्यादि

आपराधिक अपील संख्या 3528-3534/2025

14 अगस्त 2025

[जे. बी. परदीवाला और आर. महादेवन, न्यायमूर्ति गण]

विचारणीय मुद्दा

क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120ख और 34 के तहत गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में प्रतिवादी-अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश विकृत और कानूनी रूप से अस्थिर है, जो जमानत को रद्द करने का कारण बन रहा है।

शीर्ष टिप्पणियाँ

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 439- जमानत रद्द करना- कब न्यायसंगत है- सह-अभियुक्त के साथ एक मशहूर हस्ती अभियुक्त संख्या 2 पर अन्य सह- अभियुक्तों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, 364, 302, 201 और 204 के तहत एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसे अभियुक्त संख्या 2 के साथी अभियुक्त संख्या 1 को आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए अभियुक्त द्वारा कथित रूप से अपहरण, यातना और पीट-पीट कर मार दिया गया था- उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को जमानत दी गई- औचित्य:

अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय का आदेश गंभीर कानूनी दुर्बलताओं से ग्रस्त है- भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120ख और 34 के तहत आरोपों से जुड़े मामले में जमानत देने के लिए कोई विशेष या ठोस कारण नहीं दिए गए हैं, जो विवेकाधिकार के एक यांत्रिक अभ्यास को दर्शाता है, जो कानूनी रूप से प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों की महत्वपूर्ण चूक द्वारा चिह्नित किया गया है- आरोप एक युवक की क्रूर और हिरासत में हत्या का है, जिसे आरोपी द्वारा कथित रूप से अपहरण, यातना और पीट-पीट कर मार दिया गया था- यह अचानक उकसाने या भावनात्मक प्रकोप का मामला नहीं है- साक्ष्य एक

पूर्व-नियोजित और सुनियोजित अपराध का संकेत देता है जहां आरोपी भी साक्ष्यों के व्यवस्थित विनाश में शामिल था- अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर पर्याप्त विचार किए बिना, आरोपी की भूमिका और मुकदमे में हस्तक्षेप का ठोस जोखिम, एक प्रतिकूल और पूरी तरह से अनुचित अभ्यास के बराबर है- उच्च न्यायालय द्वारा गवाहों को धमकी देने के लिए, धमकी देने के आरोप को स्पष्ट करने के लिए एक कारक के रूप में माना जाता है। बाध्यकारी फोरेंसिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ, जमानत को रद्द करने की आवश्यकता को और मजबूत करता है- इसके अलावा, विवादित आदेश के तहत दी गई स्वतंत्रता न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के लिए एक वास्तविक और आसन्न खतरा पैदा करती है और परीक्षण प्रक्रिया को पटरी से उतारने का जोखिम उठाती है-अभियुक्त संख्या 2 की पृष्ठभूमि, प्रभाव, जेल कदाचार, और उसके खिलाफ आरोपों की गंभीरता उसे जमानत के लिए अयोग्य बनाती है, और उसे जमानत देने का आदेश, जहां दिमाज का इस्तेमाल किए बिना, विकृत है, और इसलिए, कानूनी रूप से अस्थिर है- वर्तमान मामला धारा 439(2) के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए कहता है- विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया- प्रतिवादियों को दी गई जमानत रद्द कर दी गई है। [अनुच्छेद 20.1.4,22.1.3-22.1.5]

जमानत – भारत का संविधान – अनुच्छेद 14 – जमानत के मामलों में मशहूर व्यक्तियों को कोई विशेष व्यवहार नहीं:

अभिनिर्धारित : भारत का संविधान अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है, और यह आदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अमीर, प्रभावशाली या प्रसिद्ध क्यों न हो, कानून की सख्ती से छूट का दावा नहीं कर सकता – एक मशहूर हस्ती का दर्जा किसी आरोपी को कानून से ऊपर नहीं उठाता, न ही उसे जमानत देने जैसे मामलों में विशेष व्यवहार का हकदार बनाता है– मशहूर हस्तियां सामाजिक अनुकरणीय व्यक्ति होते हैं, उनकी जवाबदेही कम नहीं, बल्कि ज़्यादा होती है– प्रसिद्धि और सार्वजनिक उपस्थिति के कारण, वे सार्वजनिक व्यवहार और सामाजिक मूल्यों पर काफी प्रभाव डालते हैं – साजिश और हत्या जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद ऐसे व्यक्तियों से नरमी बरतना, समाज को गलत संदेश भेजता है और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करता है – लोकप्रियता माफी के लिए ढाल नहीं हो सकती – प्रभाव, संसाधन और सामाजिक स्थिति जमानत देने का आधार नहीं बन सकते, जहां जांच या मुकदमे में पूर्वाग्रह का वास्तविक खतरा हो – अभियुक्त संख्या 2 एक आम विचाराधीन कैदी नहीं है – वह मशहूर हस्ती है, उसके बड़े पैमाने पर प्रशंसक हैं, राजनीतिक प्रभाव और वित्तीय ताकत रखता है – जेल के अंदर उसका आचरण, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को दी जाने वाली विशेष सुविधा के दर्ज किए गए मामले, जेल नियमों का

उल्लंघन, और सुविधाओं के दुरुपयोग के लिए दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल हैं, यह दर्शाता है कि वह हिरासत में रहते हुए भी व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता रखता है – यदि कोई व्यक्ति जेल प्रणाली को कमजोर कर सकता है, तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़, गवाहों को धमकाने या प्रभावित करने, और न्याय की प्रक्रिया में हेरफेर का खतरा वास्तविक और आसन्न है – जमानत पर होने के बावजूद अभियुक्त संख्या 2 का तुरंत सामाजिक कार्यक्रमों में लौटना, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ मंच साझा करना, और पुलिस गवाहों पर लगातार प्रभाव, यह साबित करता है कि उसकी स्वतंत्रता कार्यवाही की निष्पक्षता के लिए खतरा है – आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों में, जमानत न्यायालय को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए – हालांकि, उच्च न्यायालय के आदेश में आरोप की गंभीरता और मामले के व्यापक सामाजिक प्रभाव के बावजूद, ऐसी कोई उच्च जांच या सतर्क दृष्टिकोण परिलक्षित नहीं होता है – न्याय वितरण प्रणाली। [अनुच्छेद 22.4.5, 23, 23.5-23.8]

जमानत – जमानत के स्तर पर अदालतें मामले के गुण-दोष पर निष्कर्ष नहीं देंगी:

अभिनिर्धारित : न्यायालयों को साक्ष्यों की विस्तृत जांच करने या ऐसे निष्कर्ष देने से रोका गया है जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित करते हों– केवल सामग्री का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन ही उचित है– न्यायालय लघु-विचारण नहीं कर सकती या ऐसे निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकती जो विचारण के परिणाम को प्रभावित कर सकें – विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष में जाकर और ऐसे निष्कर्ष दर्ज करके आरोपी को जमानत दे दी जो विशेष रूप से विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। [अनुच्छेद 20.2.1, 20.2.4]

जमानत – कब रद्द या समाप्त की जा सकती है – आदेश में कानूनी कमी के कारण जमानत का रद्द होना; जमानत का रद्द होना यानी जमानत के बाद आरोपी का व्यवहार या जमानत के बाद की परिस्थितियों के कारण जमानत का निरस्तीकरण – न्यायशास्त्र का परीक्षण [अनुच्छेद 18.1-19]

जमानत – भारत का संविधान – अनुच्छेद 22(1) – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 50 – गिरफ्तारी के आधार बताने में प्रक्रियात्मक चूक, बिना किसी पूर्वाग्रह के, अपने आप हिरासत को अवैध नहीं बनाती या आरोपी को जमानत का हकदार नहीं बनाती – प्रतिवादियों-आरोपियों का यह तर्क कि गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि गिरफ्तारी के आधार तुरंत लिखित रूप में नहीं बताए गए थे, जो अनुच्छेद 22(1) और धारा 50, आपराधिक प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन है:

अभिनिर्धारित : संवैधानिक और वैधानिक ढांचा यह अनिवार्य करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए जाने चाहिए– लेकिन कोई भी प्रावधान किसी विशिष्ट रूप को निर्धारित नहीं करता है या हर मामले में लिखित संचार पर जोर नहीं देता है – इन आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त है, जब तक कि स्पष्ट पूर्वाग्रह न दिखाया जाए– केवल लिखित आधारों की अनुपस्थिति अपने आप गिरफ्तारी को अवैध नहीं बनाती है, जब तक कि इससे स्पष्ट पूर्वाग्रह या बचाव का उचित अवसर न मिले– वर्तमान मामले में, गिरफ्तारी ज्ञापन और हिरासत के अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रतिवादियों को उनकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी थी– उन्हें शुरू से ही कानूनी प्रतिनिधित्व मिला था और गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत के लिए आवेदन किया था, जो आरोपों की तत्काल और सूचित समझ को दर्शाता है–अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह स्थापित करे कि कथित प्रक्रियात्मक चूक के कारण कोई पूर्वाग्रह हुआ – उच्च न्यायालय ने इसे एक निर्णायक कारक माना, जबकि धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप की गंभीरता और प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। [अनुच्छेद 20.1.3, 20.1.5, 20.1.7]

जमानत – आरोप-पत्र दाखिल करना, जमानत देने का औचित्य नहीं है:

अभिनिर्धारित : केवल आरोप-पत्र दाखिल करने से जमानत का अकाट्य अधिकार नहीं मिलता है– इसी तरह, केवल लंबे मुकदमे की संभावना अपने आप में अपराध की गंभीरता, जांच के दौरान एकत्र किए गए आपत्तिजनक साक्ष्य , या गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से अधिक नहीं हो सकती है। [अनुच्छेद 20.4.1, 20.4.6]

जमानत– साक्ष्य- जमानत के चरण में, मूल्यांकन – अस्वीकार्य। [अनुच्छेद 20.3.1-20.3.6]

जमानत – चिकित्सीय आधार पर, विश्वसनीय, विशिष्ट और तत्काल ज़रूरत पर आधारित होनी चाहिए, न कि सामान्य या भविष्य की आशंकाओं पर:

अभिनिर्धारित : चिकित्सीय आधारों को गलत तरीके से पेश करके जमानत हासिल की गई– चिकित्सीय विवरण और आरोपी के बाद के आचरण की सरसरी जांच से पता चलता है कि चिकित्सीय दलील गुमराह करने वाली, अस्पष्ट और बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई थी– अभियुक्त संख्या 2 यह साबित करने में विफल रहा कि जेल चिकित्सालय उसकी स्थिति को संभालने में असमर्थ था या न्यायिक हिरासत में पर्याप्त इलाज नहीं दिया जा सकता था– उच्च न्यायालय ने हिरासत में इलाज की तात्कालिकता, गंभीरता या अपर्याप्तता पर कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज किए बिना जमानत दे दी, जिसके

परिणामस्वरूप एक विकृत और कानूनी रूप से अस्थिर जमानत आदेश जारी हुआ, जिसे रद्द किया जा सकता है। [अनुच्छेद 22.3.1, 22.3.6]

जमानत– जमानत के बाद आरोपी का अच्छा आचरण, हालांकि जमानत जारी रखने के सवाल के लिए प्रासंगिक है, फिर भी, अन्यथा अस्थिर आदेश को पूर्वव्यापी रूप से मान्य नहीं करता है:

अभिनिर्धारित: जबकि जमानत के बाद अच्छा आचरण या कारावास की अवधि जमानत जारी रखने के चरण में प्रासंगिक विचार हो सकते हैं, वे जमानत देने वाले आदेश में मौलिक दोषों को ठीक नहीं कर सकते हैं जो अन्यथा विकृत, कानूनी रूप से अस्थिर है, या अपराध की गंभीरता, प्रथम दृष्टया संलिप्तता, और गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर उचित विचार किए बिना पारित किया गया है– एक अस्थिर जमानत आदेश केवल समय बीतने या आरोपी के बाद के व्यवहार से मान्य नहीं हो जाता है– न्यायिक जांच इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि जमानत देने का विवेक विवेकपूर्ण तरीके से और स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, अनुदान के समय प्रयोग किया गया था, न कि यांत्रिक रूप से या तकनीकी आधार पर– यह तथ्य कि आरोपी 140 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में थे, या रिहाई के बाद अच्छा आचरण प्रदर्शित किया, यह अपने आप जमानत के आदेश को टिकाऊ नहीं बनाता है, यदि यह अनुदान के चरण में महत्वपूर्ण कारकों पर विचार न करने से ग्रस्त है– प्रतिवादी- आरोपियों को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया गया। [अनुच्छेद 20.5.1, 20.5.6]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) **[2024] 6 एससीआर 666 : (2024) 8 एससीसी 254;** पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया **[2023] 12 एससीआर 714: (2024) 7 एससीसी 576 – लागू नहीं माना गया।**

महिपाल बनाम राजेश कुमार **[2019] 14 एससीआर 529: (2020) 2 एससीसी 118**; दौलत राम बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा **[1994] पूरक 6 एससीआर 69: (1995) 1 एससीसी 349;** राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम संजय गांधी [**1978] 3 एससीआर 950 : (1978) 2 एससीसी 411**; प्रहलाद सिंह भाटी बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) **[2001] 2 एससीआर 684 : (2001) 4 एससीसी 280**; पूरन बनाम रामबिलास और अन्य **[2001] 3 एससीआर 432 : (2001) 6 एससीसी 338**; डॉ. नरेंद्र के. अमीन बनाम गुजरात राज्य और अन्य [2008] **6 एससीआर 1149 : 2008 (6) स्केल 415;**

प्रसंता कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी **[2010] 12 एससीआर 1165 : (2010) 14 एससीसी 496**; प्रकाश कदम और अन्य बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता और अन्य **[2011] 6 एससीआर 800: (2011) 6 एससीसी 189;** नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[2014] 12 एससीआर 453 : (2014)**

16 एससीसी 508; अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) **[2017] 11 एससीआर 195 : (2018) 12 एससीसी 129;** केरल राज्य बनाम महेश **[2021] 2 एससीआर 964 : एआईआर 2021 एससी 2071;** अब्दुल बासित बनाम अब्दुल कादिर चौधरी **[2014] 10 एससीआर 571: (2014) 10 एससीसी 754;** दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **[2022] 4 एससीआर 1: आपराधिक अपील संख्या 861/2022 @ एसएलपी(आपराधिक) संख्या 9655/2021 दिनांक 20.05.2022;** पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, **2025 आईएनएससी 482: [2025] 5 एससीआर 522**; विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य, **2025 एससीसी ऑनलाइन SC 456;** कासिरेड्डी उपेंद्र रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, **2025 आईएनएससी 768 : [2025] 7 एससीआर 105**; निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे **[1980] 3 एससीआर 15 : (1980) 2 एससीसी 559;** कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन @ पप्पू यादव **(2004) 7 एससीसी 528;** सतीश जग्गी बनाम छत्तीसगढ़ **राज्य [2007] 5 एससीआर 1049: (2007) 11 एससीसी 195;** कंवर सिंह मीना बनाम राजस्थान राज्य **[2012] 10 एससीआर 847: (2012) 12 एससीसी 180;** बृजमनी देवी बनाम पप्पू कुमार **[2021] 9 एससीआर 533 : SLP (आपराधिक) संख्या 6335 और 7916/2021 दिनांक 17.12.2021;** दिनेश एम.एन. (एसपी) बनाम गुजरात राज्य **[2008] 6 एससीआर 1134 : एआईआर 2008 SC 2318;** ओडिशा राज्य बनाम महिमानंद मिश्रा, **2018 आईएनएससी 827: आपराधिक अपील संख्या 1175/2018 दिनांक 18.09.2018;** नरेश कुमार मंगला बनाम अनीता अग्रवाल, **एआईआर 2021 एससी 277;** ईश्वरजी नागाजी माली बनाम गुजरात राज्य और अन्य [**2022] 2 एससीआर 694: आपराधिक अपील संख्या 70/2022 दिनांक 18.01.2022;** इमरान बनाम मोहम्मद भावा **[2022] 2 एससीआर 1093: आपराधिक अपील संख्या 658 और 659/ 2022 @ एसएलपी (आपराधिक) संख्या 27 और 1242/ 2022 दिनांक 22.04.2022;** राहुल गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य, **आपराधिक अपील संख्या 1343-44/2023 दिनांक 04.05.2023; राज्य सीबीआई के माध्यम से बनाम अमरमणि त्रिपाठी [2005] पूरक 3 एससीआर 454: (2005) 8 एससीसी 21;** ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह @ लल्ला बहू और अन्य **[2012] 7 एससीआर 584: (2012) 9 एससीसी 446;** अजवर बनाम **वसीम [2024] 5**

एससीआर 575: (2024) 10 एससीसी 768; राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह [**2002] 2 एससीआर 526 : (2002) 3 एससीसी 598;** पंचानन मिश्रा बनाम दिगंबर मिश्रा **[2005] 1 एससीआर 484 : (2005) 3 एससीसी 143;** जगन किशोर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, **2003 क्रिमिनल लॉ जनरल 1919**; पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य **[2022] 3 एससीआर 823: (2022) 15 एससीसी 211**; उत्तर

प्रदेश राज्य वी. नरेंद्र नाथ सिन्हा (**2019) 10 एससीसी 528;** समरेंद्र नाथ भट्टाचार्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **(2004) 11 एससीसी 165;** महाराष्ट्र राज्य बनाम धनेंद्र श्रीराम भुरले [**2009] 3 एससीआर 143: (2009) 11 एससीसी 541;** वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई **[2013] 3 एससीआर 547: (2013) 7 एससीसी 439**; राणा कपूर बनाम प्रवर्तन निदेशालय **(2022) 8 एससीसी 1– पर भरोसा किया गया।**

संत श्री आसाराम बापू बनाम राजस्थान राज्य, **2015 एससीसी ऑनलाइन एससी 1903;** राम किशोर अरोड़ा बनाम प्रवर्तन निदेशालय [**2023] 16 एससीआर 743: (2024) 7 एससीसी 599;** रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [**2012] 6 एससीआर 688 : (2012) 5 एससीसी 777 – का उल्लेख किया गया।**

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय दंड संहिता, 1860; भारत का संविधान।

प्रमुख शब्दों की सूची

धारा 439, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; हत्या; जमानत रद्द करना; मशहूर हस्ती; मशहूर हस्ती का दर्जा ; अभिनेता; अपराध की प्रकृति और गंभीरता; कथित अपराध की गंभीरता और जघन्य प्रकृति; एक युवक की क्रूर और हिरासत में हत्या; गंभीर मामलों में जमानत; जमानत के बाद अच्छा आचरण या कारावास की अवधि; पूर्ववृत्त; प्रभाव; जेल में दुर्व्यवहार; आरोपों की गंभीरता; साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना; गवाहों को प्रभावित करना; चिकित्सीय आधार पर गलत बयानी करके जमानत प्राप्त करना ;

उच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार न करना; पूर्व नियोजित और सुनियोजित अपराध; पूर्व नियोजित हत्या और साजिश; सह-आरोपी को झूठा आत्मसमर्पण करने के लिए रिश्वत देना; आरोपी

बड़ा हो या छोटा; न्याय वितरण प्रणाली; कानून का शासन; साक्ष्यों को नष्ट करना; आपत्तिजनक संदेश; अश्लील संदेश।

मामले की उत्पति

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्याएँ 3528-3534/2025

2024 के सीआरएलपी संख्या 11096, 11176, 11180, 11212, 11282, 11735 और 12912 में बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 13.12.2024 से

अधिवक्तागण

अधिवक्तागण अपीलकर्ता के लिए:

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. एल. चिदानंद, पी प्रसन्ना कुमार, अनिल सी निशानी, सचिन, मिहिर जोशी, मंथन दयानद, गौरव चौहान, विश्वेश आर मुरनाल, रविंदर कुमार वर्मा, इशान रॉय चौधरी, माधव बी. कश्यप, राहुल के. रेड्डी।

अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए:

सिद्धार्थ दवे, गौरव अग्रवाल, के. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री तनीषा कौशल, हिमांशु त्यागी, अश्विन वैश्य, सुनील कुमार एस, आशुतोष ठाकुर, अजय आर, तरूण शर्मा, वी थॉमस, सुश्री शुबी विजयवर्गीय, उत्तम पंवार, आदित्य शर्मा, अनुरूप चक्रवर्ती, सुश्री अमृता शर्मा, चंद्र प्रताप, परीक्षित अंगड़ी, अनिरुद्ध सांगानेरिया, सुनील कुमार एस, लक्ष्मीकांत जी, एच. चंद्र शेखर, सुश्री। संजना सैड्डी, आदित्य डी, हितेश गौड़ा, संतोष यू, सुश्री मृणाल कंवर, अभिषेक सांडिल्य, वैभव राजसिंह राठौड़।

सर्वोच्च न्यायलाया का निर्णय/आदेश

निर्णय

आर. महादेवन, न्यायमूर्ति

अनुमति प्रदान की गई

2. यहां अपीलकर्ता कर्नाटक राज्य है, जिसने बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 11096/2024 और छह संबंधित मामलों में 13.12.2024 को पारित सामान्य आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत प्रतिवादियों/आरोपी संख्या 1, 2, 6, 7, 11, 12 और 14 को कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु शहर में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120बी, 364, 384, 355, 302, 201, 143, 147, 148, 149 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अपराध संख्या 250/2024 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

3. सुरवात में, यह मामला 09.06.2024 को सतवा अनुग्रह अपार्टमेंट, सुमनहल्ली, बेंगलुरु के सुरक्षा अधिकारी केवल राम दोरजी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302 और 201 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था, जब उक्त अपार्टमेंट के सामने नाले के पास सड़क किनारे लगभग 30 से 35 वर्ष के एक अज्ञात पुरुष का शव, जिस पर चोट के निशान थे, मिला था।

4. जांच के दौरान, आरोपी संख्या 1, 2, 11, 12 और 14 को 11.06.2024 को गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोपी संख्या 6 और 7 को 14.06.2024 को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच पूरी होने पर, कुल

17 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया, और क्षेत्राधिकार न्यायालय में एक आरोप-पत्र के साथ दो पूरक आरोप-पत्र दायर की गईं।

5. वर्तमान प्रतिवादियों के खिलाफ लगाए गए खास आरोप नीचे दिए गए हैं:

आरोपी संख्या	नाम	भारतीय दंड संहिता के तहत धारा
2	दर्शन @ डी. बॉस, अभिनेता	302,34,120बी,355,143,147, 148,149,201,364
11	नागराजू आर.	149, 201, 302, 34, 120बी,143, 147, 148, 355
7	अनु कुमार@ अनु, ड्राइवर	149, 201, 364, 384, 302, 34, 120बी, 143, 147, 148
12	लक्ष्मण एम. ड्राइवर	149, 201, 302, 34, 120बी, 143, 147, 148
1	पवित्रा गौड़ा	120बी, 355, 143, 147, 148, 149, 201, 364, 302, 34

6	जगदीश@ जग्गा, ड्राइवर	149, 201, 364, 384, 302, 34, 120बी, 143, 147, 148
14	प्रदूष एस. राव@ प्रदूष	120बी,143,147,148,149, 201, 302, 34

6. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

6.1. कथित तौर पर अभियुक्त संख्या 1 का अभियुक्त संख्या 2 के साथ संबंध था। मृतक, रेणुकास्वामी, जो चित्रदुर्ग का रहने वाला था, ने कथित तौर पर फरवरी 2024 से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अभियुक्त संख्या 1 के अकाउंट पर अश्लील मैसेज भेजे थे। इससे नाराज़ होकर, अभियुक्त संख्या 1, अभियुक्त संख्या 2, अभियुक्त संख्या संख्या 3 (जो अभियुक्त संख्या 1 और अभियुक्त संख्या 2 के घर में काम करता था), और अभियुक्त संख्या 10 (अभियुक्त संख्या 2 का दोस्त) ने कथित तौर पर दूरभाष पर बातचीत के ज़रिए मृतक का पता लगाने, उसका अपहरण करने और उसकी हत्या करने की साज़िश रची।

6.2. इस साज़िश के तहत, अभियुक्त संख्या 1 ने कथित तौर पर 03.06.2024 को इंस्टाग्राम के ज़रिए मृतक से संपर्क किया और उसका फ़ोन नंबर मांगा। जवाब में, मृतक ने उसका फ़ोन नंबर मांगा। मृतक के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और योजना को आगे बढ़ाने के इरादे से, अभियुक्त संख्या 1 ने इसे अपना नंबर बताते हुए, मोबाइल नंबर 9535289797 (जो असल में अभियुक्त संख्या 3 का था) इंस्टाग्राम के ज़रिए मृतक को भेजा।

6.3. इसके बाद, 05.06.2024 को सुबह लगभग 9.00 बजे, मृतक ने अभियुक्त संख्या 3 के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया, यह मानते हुए कि यह अभियुक्त संख्या 1 का नंबर है। लगातार व्हाट्सप्प बातचीत के ज़रिए, उसने अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर की, जिसमें उसकी लोकेशन (चित्रदुर्ग), काम करने की जगह (अपोलो फ़ार्मेसी), और फ़ोटो शामिल थी।

6.4. आरोप है कि अभियुक्त संख्या 3 ने यह जानकारी अभियुक्त संख्या 1, अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 10 साथ साझा की, और साज़िश में अभियुक्त संख्या 2 के प्रशंसक साथियों को भी शामिल किया गया। अभियुक्त संख्या 2 ने अपने साथियों, जिसमें अभियुक्त संख्या 4 भी शामिल था, के ज़रिए उन्हें निर्देश दिया कि मृतक का अपहरण करें और उसे उनके पास ले आएं। इसके बाद, उन्होंने उस पर हमला करने और उसे मारने का प्लान बनाया। इसके बाद, अभियुक्त संख्या 3 ने अभियुक्त संख्या 4 को संपर्क किया और उसे निर्देश दिया कि मृतक को ढूंढे, उसका अपहरण करे, और उसे

अभियुक्त संख्या 2 के घर ले आए। अभियुक्त संख्या 4 ने यह योजना अपने दोस्तों और चित्रदुर्ग के अभियुक्त संख्या 2 के प्रशंसक– अभियुक्त संख्या 6 और अभियुक्त संख्या 7 और को बताया।

6.5. दिनांक 07.06.2024 को, अभियुक्त संख्या 1, अभियुक्त संख्या 2, और अभियुक्त संख्या 10 के निर्देशों के बाद, अभियुक्त संख्या 3 ने के ज़रिए मृतक से संपर्क किया और उसे पता चला कि वह न्यायालय के पास है। फिर अभियुक्त संख्या 3 ने अभियुक्त संख्या 4

को बताया, जो अभियुक्त संख्या 6 और अभियुक्त संख्या 7 के साथ, मृतक को ढूंढने के लिए न्यायालय परिसर में गया। हालाँकि, वे उसे ढूंढने में कामयाब नहीं हुए।

6.6. दिनांक 08.06.2024 को, अभियुक्त संख्या 6 ने मृतक के घर का पता लगाया और अभियुक्त संख्या 7 और अभियुक्त संख्या 8 को उस जगह बुलाया। वे उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसे अपहरण करने की तैयारी में। कुछ देर बाद, मृतक अपनी दोपहिया गाड़ी से घर से निकला। अभियुक्त संख्या 4, अभियुक्त संख्या 6, और अभियुक्त संख्या 7 ने अभियुक्त संख्या 6 के ऑटो रिक्शा (रजिस्ट्रेशन नंबर केए 16 एए 3421) में उसका पीछा किया। सुबह लगभग 10.00 बजे, उन्होंने उसे बालाजी बार, चित्रदुर्ग के पास से अपहरण किया, और उसे राजमार्ग के बाहरी इलाके में भारत पेट्रोल पम्प के पास एक खुली जगह पर ले गए। फिर उसे अभियुक्त संख्या 8 की एक इटियोस कार (पंजीकरण संख्या केए -11-बी -7939) में बिठाया गया, और उसे आरआर नगर में इंटैक्ट ऑटो पैकर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे एक शेड में लाया गया, जो कथित तौर पर अभियुक्त संख्या 13 के नियंत्रण में था।

6.7. इसके बाद, आरोपी आगे की योजना पर चर्चा करने के लिए स्टोनी ब्रूक रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए। इसी बीच, अभियुक्त संख्या 3 शेड पर पहुंचा और उसने मृतक को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। अभियुक्त संख्या 5 ने भी उसे मारा और ज़मीन पर गिरा दिया, और अभियुक्त संख्या 4, अभियुक्त संख्या 6 और अभियुक्त संख्या 7 ने उसे टहनियों से पीटा। अभियुक्त संख्या 9 ने मृतक के सिर पर मारा और उसकी छाती, पीठ, बांहों और पैरों पर इलेक्ट्रिक शॉक टॉर्च (मेगर) का इस्तेमाल किया।

6.8. शाम करीब 4.45 बजे, अभियुक्त संख्या 2, अभियुक्त संख्या 1, अभियुक्त संख्या 13, अभियुक्त संख्या 10, अभियुक्त संख्या 11 और अभियुक्त संख्या 14 के साथ दो स्कॉर्पियो गाड़ियों में शेड पर पहुंचा। आरोपियों ने एक गैर-कानूनी भीड़ बनाकर मृतक पर और हमला किया। अभियुक्त संख्या 2 ने कथित तौर पर मृतक को मुक्के मारे, लातें मारीं और पेड़ की टहनी से पीटा। उस पर नायलॉन की

रस्सी और लकड़ी की टहनियों से भी हमला किया गया। अभियुक्त संख्या 5 ने कथित तौर पर मृतक का सिर अशोक लेलैंड दोस्त गाड़ी के बंपर से टकरा दिया, जिससे सिर से खून बहने लगा। अभियुक्त संख्या 1 ने उसे अपनी चप्पलों से मारा और उसे अपने पैर छूने के लिए मजबूर किया, जबकि दूसरों को उसे जान से मारने के लिए उकसाया।

6.9. अभियुक्त संख्या 11 ने कथित तौर पर उसे अपनी चप्पल और नायलॉन की रस्सी से बार-बार मारा। अभियुक्त संख्या 12 ने अपने मुक्कों से और जानलेवा हमले किए। अभियुक्त संख्या 1 के जाने के बाद, अभियुक्त संख्या 13 शेड पर पहुंचा। अभियुक्त संख्या 2 ने अभियुक्त संख्या 14 को मृतक का मोबाइल फोन जांच करने के लिए कहा, जिसमें पता चला कि उसने कई महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजे थे। इसके बाद अभियुक्त संख्या 2 ने कथित तौर पर उसके पेट में मुक्का मारा, अपने जूते से उसकी छाती दबाई, और उसके बाएं कान और सिर पर लात मारी, जिससे खून बहने लगा।

6.10. इसके अलावा, अभियुक्त संख्या 2 ने अभियुक्त संख्या 3 को मृतक की पैंट उतारने का निर्देश दिया और फिर अपने जूते से उसके गुप्तांगों पर लात मारी। अभियुक्त संख्या 3, अभियुक्त संख्या 4, अभियुक्त संख्या 5, अभियुक्त संख्या 6, अभियुक्त संख्या 7, अभियुक्त संख्या 10, अभियुक्त संख्या 11, अभियुक्त संख्या 12 और अभियुक्त संख्या 14 ने कथित तौर पर हाथों, लकड़ी की छड़ियों, लाठियों, नायलॉन की रस्सियों और अन्य चीज़ों से मृतक पर हमला करना जारी रखा, जिससे उसकी पीठ, बांहों, पैरों और छाती पर गंभीर चोटें आईं। मृतक की मौके पर ही चोटों के कारण मौत हो गई। इसके बाद अभियुक्त संख्या 4 और अभियुक्त संख्या 5 ने शव को शेड के अंदर सुरक्षा कक्ष में रख दिया।

6.11. इसके बाद, अभियुक्त संख्या 2 ने कथित तौर पर दूसरों को शव को चुपचाप ठिकाने लगाने का निर्देश दिया, और खर्च उठाने का वादा किया। फिर अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 10 अभियुक्त संख्या 2 की रैंगलर जीप में चले गए। बाद में, अभियुक्त संख्या 10, अभियुक्त संख्या 11, अभियुक्त संख्या 12 और अभियुक्त संख्या 14 शेड में लौटे और अभियुक्त संख्या 2 के निर्देशों का पालन करते हुए, एक झूठी समर्पण कहानी बनाने पर चर्चा की। अभियुक्त संख्या 2 पर यह भी आरोप है कि उसने साक्ष्यों को छिपाने और खुद को और अभियुक्त संख्या 1 को फंसाने से बचने के लिए अभियुक्त संख्या 14 को 30 लाख रुपये, अभियुक्त संख्या 10 को 10 लाख रुपये और अभियुक्त संख्या 11 को 5 लाख रुपये दिए। अभियुक्त संख्या 15 और अभियुक्त संख्या 17 कथित तौर पर पैसे के बदले समर्पण करने के लिए सहमत हो गए।

6.12. दिनांक 09.06.2024 की सुबह, अभियुक्त संख्या 10, अभियुक्त संख्या 11, अभियुक्त संख्या 12, अभियुक्त संख्या 13, और अभियुक्त संख्या 14 ने अभियुक्त संख्या 4, अभियुक्त संख्या 6, अभियुक्त संख्या 7, अभियुक्त संख्या 8, अभियुक्त संख्या 15 और अभियुक्त संख्या 17 की मदद से, अभियुक्त संख्या 11 द्वारा लाई गई स्कॉर्पियो गाड़ी में मृतक के शव को ले जाकर साक्ष्यों को नष्ट करने और जांच को गुमराह करने के इरादे से

सतवा अनुग्रह अपार्टमेंट, सुमनहल्ली, बेंगलुरु के सामने एक बरसाती नाले के पास फेंक दिया। इसके बाद, अभियुक्त संख्या 4, अभियुक्त संख्या 15, अभियुक्त संख्या 16 और अभियुक्त संख्या 17 ने कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया।

7. पोस्टमार्टम परीक्षण के अनुसार, मृतक को 39 चोटें आईं, जिनमें से 13 खून बहने वाली चोटें थीं और 17 पसलियां टूटी हुई थीं।

8. प्रतिवादियों/आरोपियों ने पहले बेंगलुरु (सीसीएच -57) में एलवीआई अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश के पास आपराधिक विविध याचिका संख्या 8580/2024, 8770/2024, 9126/2024, 8812/2024, 8799/2024, 8798/2024 और 9120/2024 दायर करके जमानत मांगी थी, जिन्हें सभी खारिज कर दिया गया था।

9. उनकी ज़मानत याचिकाएं खारिज होने पर, प्रतिवादियों/आरोपियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत आपराधिक याचिका संख्या 11096/2024, 11176/2024, 11180/2024, 11212/2024, 11282/2024, 11735/2024,और 12912/2024 दायर करके उच्च न्यायालय का रुख किया। अभियुक्त संख्या 2 ने चिकित्सीय आधार पर अंतरिम ज़मानत भी मांगी, जो जेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर 15.10.2024 को छह सप्ताह के लिए दी गई।

10. आखिरकार, उच्च न्यायालय ने आपराधिकयाचिकाओं को स्वीकार कर लिया और 13.12.2024 के विवादित आदेश द्वारा प्रतिवादियों/आरोपियों को ज़मानत पर रिहा कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, राज्य ने वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

11. अपीलकर्ता – राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने शुरू में ही यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित 13.12.2024 का विवादित आदेश प्रथम दृष्टया अस्थिर है क्योंकि यह

विवरण पर मौजूद महत्वपूर्ण साक्ष्यों के विपरीत है और इसमें शामिल तथ्यों और कानून पर गंभीर रूप से विचार नहीं किया गया है।

11.1. जहां तक प्रतिवादी (अभियुक्त संख्या 2) को चिकित्सीय आधार पर ज़मानत देने का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

(i) 24.10.2024 की चिकित्सीय राय में शल्य चिकित्सा का प्रकार, शल्य चिकित्सा की संभावित तारीख, उसकी प्रकृति, या आवश्यक शल्य चिकित्सा के बाद देखभाल का खुलासा नहीं किया गया था। अस्पष्टता और किसी भी तात्कालिकता के संकेत के अभाव के बावजूद, उच्च न्यायालय ने दावे की सच्चाई का आकलन करने के लिए चिकित्सीय बोर्ड का गठन किए बिना ही, पहले प्रतिवादी को छह सप्ताह की अवधि के लिए चिकित्सीय जमानत पर रिहा कर दिया। **यह संत श्री आसाराम बापू बनाम राजस्थान राज्य**[4] में तय किए गए कानून के विपरीत है, जिसमें यह माना गया था कि चिकित्सीय जमानत देने से पहले विशेषज्ञ चिकित्सीय राय आवश्यक है।

(ii) इसके बाद, उच्च न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बाद भी कोई शल्य चिकित्सा या महत्वपूर्ण इलाज नहीं करवाया था। न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा और इसके बजाय यह टिप्पणी की कि आरोपी के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। प्रतिवादी का विरोधाभासी आचरण इस तथ्य से स्पष्ट है कि हालांकि उसने दावा किया था कि शल्य चिकित्सा दिनांक 11.12.2024 को निर्धारित थी, लेकिन यह इस मनगढ़ंत आधार पर नहीं की गई कि उसका रक्तचाप स्थिर नहीं था- एक ऐसी स्थिति जिसे आमतौर पर दवा से नियंत्रित किया जा सकता है यदि शल्य चिकित्सा वास्तव में जरूरी होती।

(iii) प्रतिवादी संख्या 1 का आचरण स्पष्ट रूप से किसी भी तत्काल चिकित्सा आवश्यकता की कमी को इंगित करता है। लगातार देरी और अस्पष्ट औचित्य चिकित्सीय दावे की झूठी प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। इस प्रतिवादी ने जमानत पाने के लिए शल्य चिकित्सा की तात्कालिकता के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उच्च न्यायालय इस पर विचार करने में विफल रहा।

(iv) उच्च न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण कानून के स्थापित सिद्धांत के विपरीत है कि कोई भी पक्ष जो न्यायालय को गुमराह करता है, वह जमानत जैसी विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं है। इसलिए, उच्च

न्यायालय को प्रतिवादी/अभियुक्त संख्या 2 को नियमित जमानत देने के बजाय उसकी आपराधिक याचिका खारिज कर देनी चाहिए थी।

(v) इसके अलावा, उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि आरोप-पत्र गवाहों की लंबी सूची के कारण विचारण लंबा चलेगा, समय से पहले और अटकलबाजी पर आधारित है, और यह अपने आप में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 302, 364, 384, 201 और अन्य गंभीर प्रावधानों के तहत दंडनीय गंभीर अपराध वाले मामले में जमानत देने का आधार नहीं हो सकता।

(vi) उपरोक्त दलीलों के आधार पर, यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय का पहला प्रतिवादी को चिकित्सीय आधार पर रिहा करने का विवादित आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

11.2. आगे बढ़ते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आदेश को चुनौती देते हुए निम्नलिखित तर्क दिए:

(i) उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों और रिकॉर्ड पर मौजूद महत्वपूर्ण साक्ष्यों को समझने में गलती की। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 362 और 364 के तहत अपहरण के अपराध का ठीक से विश्लेषण करने में विफल रहा। मृतक को जबरदस्ती एक वाहन में बंद करना और उसकी इच्छा के विरुद्ध बेंगलुरु ले जाना स्पष्ट रूप से धारा 364 के दायरे में आता है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला चित्तूर से बेंगलुरु तक मृतक को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए गए धोखे भरे तरीकों को दर्शाता है, जो सीधे तौर पर धारा 362 के तहत अपहरण के अपराध को आकर्षित करता है। विद्वान न्यायाधीश ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 56/2023 में अपने ही पिछले फैसले को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती वाहन के अंदर रखना ही धारा 364 भारतीय दंड संहिता की शर्तों को पूरा करता है। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 362 पर विचार न करना एक गंभीर कानूनी चूक है।

(ii) उच्च न्यायालय ने यह मानने में भी गलती की कि जमानत पर विचार करते समय परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव इस न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है, जो यह अनिवार्य करता है कि मजबूत प्रथम दृष्टया सामग्री, विशेष रूप से हत्या जैसे गंभीर अपराधों में, जमानत के चरण में भी विधिवत तौली जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, कृत्य की क्रूरता स्पष्ट रूप से सामने आती है: पोस्टमार्टम परीक्षण में 39 बाहरी चोटें, 17 टूटी हुई पसलियां,

अंडकोष में चोट, और बिजली के झटके से यातना के अनुरूप बिजली के जलने के निशान दर्ज हैं। मृतक को लगी चोटों की प्रकृति और बहुलता स्पष्ट रूप से हत्या के इरादे का संकेत देती है।

(iii) उच्च न्यायालय ने बिना किसी ठोस स्पष्टीकरण के महत्वपूर्ण फोरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। मृतक का डीएनए प्रतिवादी नंबर 1 (अभियुक्त संख्या 2) द्वारा पहने गए जूते पर पाया गया, जिसे दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में धारा 27 के तहत किए गए खुलासे के बाद बरामद किया गया था। सीरोलॉजिकल और डीएनए परीक्षण से आगे पता चलता है कि मृतक का खून विभिन्न आपत्तिजनक वस्तुओं पर था, जिसमें एक नायलॉन की रस्सी, लाठी, सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी (अभियुक्त संख्या 11 के स्वामित्व वाली) का बूट मैट और घटनास्थल पर खड़ी अशोक लेलैंड गाड़ी के बंपर शामिल हैं। कई आरोपियों के कपड़ों पर भी खून पाया गया। कुछ आरोपियों के जूतों पर मिली मिट्टी/गाद अपराध स्थल से इकट्ठा की गई मिट्टी से मेल खाती थी। ये वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक संकेतक हैं जो अभियोजन पक्ष के संस्करण की पुष्टि करते हैं और इस प्रारंभिक चरण में इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

(iv) रिकॉर्ड पर मौजूद डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आगे अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करते हैं। टोल बूथों और अन्य स्थानों से सीसीटीवी फुटेज आरोपियों की आवाजाही और मृतक को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को स्थापित करता है। न्यायालय गवाह संख्या 91, एक प्रमुख चश्मदीद गवाह के फोन से बरामद एक तस्वीर में अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 6 हमले के बाद मृतक के पास मुद्रा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर), व्हाट्सएप संदेश, और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग स्पष्ट रूप से योजना, अपहरण की कार्रवाई, हमले के दौरान आचरण, और अपराध के बाद साक्ष्य मिटाने के प्रयासों को स्थापित करते हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड अलग-अलग डेटा बिंदु नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक साक्ष्य ढांचे के आपस में जुड़े हुए टुकड़े हैं जो एक आपराधिक साजिश की ओर इशारा करते हैं।

(v) अभियोजन पक्ष दो प्रमुख चश्मदीद गवाहों- न्यायालय गवाह संख्या 76 (किरण) और न्यायालय गवाह संख्या 91 (पुनीत) - की गवाही पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो अपराध स्थल पर मौजूद थे और जिनकी उपस्थिति की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की गई है। दोनों अपराध स्थल, एक निजी पार्किंग शेड में कार्यरत थे, और आरोपियों से अच्छी तरह परिचित थे। धारा 161 और 164 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज उनके बयान स्पष्ट रूप से हमले, यातना, और बाद में शव को ठिकाने लगाने की खुली कार्रवाई की ओर इशारा करते हैं। उनके बयान दर्ज करने में देरी को सत्यापित यात्रा रिकॉर्ड और

अन्य दस्तावेजों के माध्यम से विश्वसनीय रूप से समझाया गया है। ये गवाहियां सुसंगत और ठोस हैं, फिर भी उच्च न्यायालय ने उन्हें अनुचित रूप से खारिज कर दिया है।

(vi) इन दो सीधे गवाहों के अलावा, अन्य शेड कर्मचारियों– न्यायालय गवाह संख्या 69, न्यायालय गवाह संख्या 77, न्यायालय गवाह संख्या 78 और न्यायालय गवाह संख्या 79 ने आरोपी और उनके वाहनों के आने-जाने की पुष्टि की है। यह देखते हुए कि ये कर्मचारी 5-6 एकड़ के क्षेत्र में घटित अपराध में पालियों में काम करते थे, अलग-अलग जगहों पर उनकी मौजूदगी और सिर्फ़ आने-जाने के बारे में गवाही देने की उनकी क्षमता, न कि हमले के बारे में, समझ में आती है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उनके बयानों को नज़रअंदाज़ करके गलती की।

(vii) अभियोजन पक्ष उच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के गैर-अनुपालन के संबंध में दिए गए निष्कर्षों का भी कड़ा विरोध करता है। प्रतिवादियों को गिरफ्तारी के समय मौखिक रूप से गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे और उसके तुरंत बाद लिखित आधार दिए गए थे। यह प्रक्रिया इस न्यायालय

के **राम किशोर अरोड़ा बनाम प्रवर्तन निदेशालय**[5] और **प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)**[6] के फैसलों के अनुरूप है। गिरफ्तारी ज्ञापन, जांच सूची और सूचना दस्तावेज़ न्यायिक दंडाधिकारी के सामने विधिवत जमा किए गए थे और आरोपी से परिचित व्यक्तियों द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित किए गए थे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 50ए के तहत न्यायिक दंडाधिकारी को गिरफ्तारी की सूचना के बारे में संतुष्ट करने की आवश्यकता पूरी की गई थी। उच्च न्यायालय की यह ज़िद कि गिरफ्तारी के वास्तविक आधार न्यायालय में दायर किए जाने चाहिए, कानून में इसका कोई समर्थन नहीं है।

(viii) वास्तव में, आपराधिक याचिका संख्या 9537/2024 में, उसी माननीय न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया था कि यदि गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार मौखिक रूप से बताए जाते हैं और उसके तुरंत बाद लिखित संचार प्रदान किया जाता है, तो अनुच्छेद 22(1) के तहत आवश्यकता पूरी हो जाती है। वर्तमान मामले में बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण न्यायिक असंगति है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि सभी आरोपियों को दिए गए आधार समान थे, अस्थिर है। गिरफ्तारी के समय, जांच जारी थी और भूमिकाएँ सामने आ रही थीं। आरोपियों को दिए गए गिरफ्तारी के आधार उस समय उपलब्ध सामग्री पर आधारित थे और इसमें गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए आवश्यक बुनियादी तथ्य शामिल थे।

(ix) आरोपियों की लगातार स्वतंत्रता , विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या1 (अभियुक्त संख्या 2) मुकदमे की निष्पक्षता के लिए एक गंभीर खतरा है। अभियुक्त संख्या 2 एक सार्वजनिक हस्ती है जिसका पूरे राज्य में एक बड़ा प्रशंसक वर्ग और प्रभाव है। चिकित्सीय जमानत मिलने के बाद, उन्हें न्यायालय गवाह संख्या 80 (अभियोजन पक्ष के गवाह) के साथ घुलते-मिलते और सार्वजनिक समारोह में जाते देखा गया, जबकि उन्होंने न्यायालय के सामने गंभीर पीठ दर्द का दावा किया था। ऐसा व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अनादर दिखाता है और गवाहों को प्रभावित करने और उन पर दबाव डालने की आशंका को मजबूत करता है।

(x) यह अचानक उकसावे या हिंसा की अचानक की गई कार्रवाई का मामला नहीं है। यह एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया अपराध है, जिसका मकसद एक कथित शिकायत का बदला लेना था – कि मृतक ने कथित तौर पर अभियुक्त संख्या 1 को अश्लील मैसेज भेजे थे। इसके बाद अभियुक्त संख्या 1 और अभियुक्त संख्या 2 ने अपने साथियों (अभियुक्त संख्या 3 से अभियुक्त संख्या 17) के एक बड़े संचार तंत्र का इस्तेमाल करके मृतक को खत्म करने की साजिश रची। मृतक को झूठे बहाने से अगवा किया गया, जबरदस्ती बेंगलुरु ले जाया गया, एक शेड में बंद किया गया, और मारने से पहले उसे

बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित के उपकरणों (शॉक टॉर्च, लाठी, नायलॉन की रस्सी) की बरामदगी और आरोपियों से जब्त किए गए फोन में मिले अपराध के फोटोग्राफिक साक्ष्य इस अपराध की क्रूर प्रकृति को उजागर करते हैं।

(xi) उच्च न्यायालय ने इस आधार पर जमानत देकर भी गलती की है कि 262 गवाहों की सूची (आरोप-पत्र और पहली पूरक आरोप-पत्र के अनुसार) के कारण विचारण में देरी हो सकती है। मामला अभी-अभी सत्र न्यायालय को सौंपा गया था और अभी आरोप- निर्धारण के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था। इस शुरुआती स्तर पर देरी का उच्च न्यायालय का अनुमान काल्पनिक और अनुचित है। इसके अलावा, इसी तरह के हत्या के मामलों में, उसी माननीय जज ने इसी तरह के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पेश किए जाने पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। बिना पर्याप्त स्पष्टीकरण के यह विचलन, न्यायिक दृष्टिकोण में निरंतरता की कमी को दर्शाता है।

(xii) निष्कर्ष रूप में, साक्ष्यों का कुल भार– चश्मदीद गवाहों की गवाही, फोरेंसिक रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, और धारा 27 के तहत इकबालिया बयान– प्रतिवादियों के खिलाफ एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करते हैं। हत्या जैसे जघन्य अपराध में जमानत देना, खासकर जब इतने भारी साक्ष्य

मौजूद हों, न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर करता है और न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास को कम करता है।

(xiii) इसलिए, प्रतिवादियों को जमानत देने वाला विवादित आदेश रद्द किया जाए और अपीलें स्वीकार की जाएं।

12. प्रतिवादियों/आरोपियों की ओर से, उनके संबंधित विद्वान वकीलों द्वारा मौखिक और लिखित दलीलें दी गईं, और समेकित दलीलें इस प्रकार हैं:

(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट शुरू में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, और जांच के दौरान, आरोपी नंबर 1, 2, 11, 12 और 14 को दिनांक 11.06.2024 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अभियुक्त संख्या 6 और अभियुक्त संख्या 7 को दिनांक 14.06.2024 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, आरोपियों को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया था, लेकिन उन्हें न तो गिरफ्तारी के कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया और न ही समय पर कानूनी सलाह दी गई। रिमांड आवेदन की कोई प्रति नहीं दी गई, जिससे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा, गिरफ्तारी और हिरासत प्रक्रिया में उचित दस्तावेज़ीकरण की कमी थी, जैसे कि गिरफ्तारी ज्ञापन, अधिकारों की सूचना, और एक

वैधानिक जांच सूची। यहां तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा दायर की गई जांच सूची भी सभी आरोपियों के लिए समान और साइक्लोस्टाइल की गई है। गिरफ्तारी के संबंध में गवाह के बयान (न्यायालय गवाह संख्या 76) को बाद में दर्ज किया गया था और इसमें गिरफ्तारी के लिखित कारणों की प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। केवल मौखिक सूचना अपर्याप्त है। रिमांड आवेदन में सामान्य कथन गिरफ्तारी के वैध कारणों का स्थान नहीं ले सकते।

(ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विसंगतियां, प्रक्रियात्मक अनियमितताएं हैं, और आरोपों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रमाणिक मूल्य की कमी है। इन मुद्दों को मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों और फोरेंसिक विशेषज्ञों की प्रभावी जिरह के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

(iii) गवाहों के बयानों की सहजता और तत्परता विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, एक प्राथमिक चश्मदीद गवाह, न्यायालय गवाह संख्या 91, ने घटना के 12 दिन बाद अपना धारा 161, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दिया (घटना 08.06.2024 को; बयान 20.06.2024 को

दर्ज किया गया)। इस तरह की अत्यधिक और अस्पष्ट देरी विश्वसनीयता को कम करती है और बाद में सोची-समझी बात का संकेत देती है। अन्य चश्मदीद गवाह के बयान भी इसी तरह विरोधाभासों और देरी से ग्रस्त हैं।

(iv) अभियुक्त संख्या 2 से बरामद कपड़ों पर खून के धब्बे होने का अभियोजन पक्ष का दावा समकालीन साक्ष्य से विरोधाभासी है। कपड़े घटना के तीन दिन बाद बरामद किए गए थे, इस दौरान उन्हें धोया गया था और एक छत पर लटका हुआ पाया गया था। जब्ती के समय पंचनामा में खून के धब्बे का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे फोरेंसिक दावा संदिग्ध हो जाता है। इसी तरह की विसंगतियां अन्य सह-आरोपियों से बरामद सामग्रियों तक फैली हुई हैं।

(v) न्यायालय गवाह संख्या 76 और न्यायालय गवाह संख्या 91 के बयान, जो देरी से दर्ज किए गए हैं, उनकी विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करते हैं। उनकी प्रारंभिक चुप्पी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह **रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[7] में इस न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुरूप है कि अस्पष्ट देरी प्रमाणिक मूल्य को प्रभावित करती है। ऐसे साक्ष्य के प्रति उच्च न्यायालय का सतर्क दृष्टिकोण उचित है।

(vi) न्यायालय गवाह संख्या 7 के बयान और न्यायालय गवाह संख्या 8 (मृतक के माता-पिता) और न्यायालय गवाह संख्या 122 अभियोजन पक्ष के अपहरण के दावे का खंडन करते हैं, जिससे पता चलता है कि मृतक स्वेच्छा से सह-आरोपी के साथ एक जगह गया था और

उसने खुद खर्चे का भुगतान भी किया था। अपहरण का आरोप लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों पर भरोसा करना अभी भी विचारण का मामला है।

(vii) आरोपी को कथित तौर पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों से जोड़ने वाला कोई सीधा साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त संख्या 2 को फंसाने वाले बयान गवाहों के पहले से मौजूद होने के बावजूद, देरी से रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा, न्यायालय गवाह संख्या 69, न्यायालय गवाह संख्या 77, न्यायालय गवाह संख्या 78, और न्यायालय गवाह संख्या 79 के बयान रेणुकास्वामी की हत्या में अभियुक्त संख्या 2 को दोषी नहीं ठहराते हैं।

(viii) 11.06.2024 की शव-परीक्षण रिपोर्ट में मृतक की मौत का संभावित समय नहीं बताया गया है। अभियोजन पक्ष का न्यायालय गवाह संख्या 195 (हवलदार सुरेंद्र) द्वारा तैयार किए गए रेखा-चित्र पर भरोसा विवादित है, क्योंकि यह चिपकाई गई तस्वीरों वाला गूगल नक्शा का मुद्रित प्रति था।

(ix) अभियुक्त संख्या 2 और अन्य आरोपियों के बीच फोन पर किया संपर्क का विवरण निजी कर्मी और दोस्तों से संबंधित हैं; कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में केवल एक तय फिल्म शूट के दौरान अभियुक्त संख्या 2 का उसके आवास और होटल के कमरे से अंदर आना और बाहर जाना दिखाया गया है।

(x) अभियोजन पक्ष यह आरोप नहीं लगाता है कि प्रतिवादी नंबर 5 (अभियुक्त संख्या 1) मृतक के अपहरण या हमले में किसी भी तरह से शामिल था, न ही इस प्रतिवादी और अपहरण या हत्या के अपराध करने वाले व्यक्तियों के बीच कोई दूरभाष पर संपर्क की कोई कड़ी है। इस आरोपी पर एकमात्र आरोप यह है कि उसने मृतक को चप्पल से मारा था। यहां घटना स्थल पर केवल मौजूदगी, किसी और स्पष्ट कृत्य के अभाव में, धारा 302 भारतीय दंड संहिता की कठोरता को आकर्षित नहीं कर सकती।

(xi) सह-आरोपियों द्वारा किए गए हमलों के संबंध में बयान स्वतंत्र या समकालीन साक्ष्यों से समर्थित नहीं हैं। साक्ष्यों को नष्ट करने के आरोप जमानती अपराधों से संबंधित हैं।

(xii) अभियुक्त संख्या 12 की उपस्थिति और संलिप्तता के बारे में विरोधाभासी बयान विश्वसनीयता के मुद्दे उठाते हैं। न्यायालय गवाह संख्या 76 अपराध स्थल पर अभियुक्त संख्या 12 का उल्लेख नहीं करता है, जबकि न्यायालय गवाह संख्या 91 अभियुक्त संख्या 12 द्वारा हमले का आरोप लगाता है।

(xiii) प्रतिवादी नंबर 7 (अभियुक्त संख्या 14) झूठे फंसाए जाने का दावा करता है। आरोप कि अभियुक्त संख्या 14 को अभियुक्त संख्या 2 से 30 लाख रुपये मिले और उसने अपराध को छिपाने की साजिश रची, केवल सह-आरोपियों के बयानों पर आधारित हैं। उसकी भूमिका

धारा 201 भारतीय दंड संहिता (साक्ष्यों को गायब करना) के तहत अपराध तक सीमित है। उस पर कोई स्पष्ट कृत्य या ठोस आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं।

(xiv) आरोप-पत्र और बयान हत्या में आरोपी नंबर 6 और 7 की किसी साजिश या संलिप्तता को साबित नहीं करते हैं। उनकी भूमिका मृतक को ले जाने तक सीमित थी, और उन्हें उस पर हमला करने या उसे खत्म करने की किसी योजना के बारे में पता नहीं था।

(xv) कुल मिलाकर, प्रथम सूचना रिपोर्ट , आरोप-पत्र और बयान प्रतिवादियों द्वारा सीधे तौर पर शामिल होने का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहते हैं। आरोप अस्पष्ट हैं और प्रत्येक आरोपी

द्वारा किए गए स्पष्ट कृत्यों को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। प्रतिवादियों से जुड़े कोई हथियार या खून से सने कपड़े बरामद नहीं हुए हैं। सीरोलॉजिकल और डीएनए रिपोर्ट निर्णायक नहीं हैं। जैसा कि **महिपाल बनाम राजेश कुमार**[8] में कहा गया है, अपराध की गंभीरता अकेले जमानत रद्द करने का औचित्य नहीं ठहराती है जब तक कि आरोपी की भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित न हो जाए।

(xvi) जमानत रद्द करने का कानून अच्छी तरह से स्थापित है: हस्तक्षेप तभी उचित है जब ऐसी परिस्थितियाँ हों जैसे (i) आरोपी द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग (ii) गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास, या (iii) जमानत देने का आदेश विकृत हो या महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा करता हो। उच्च न्यायालय के तर्क से केवल असहमति अपर्याप्त है। [देखें: **दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य**[9]]।

(xvii) प्रतिवादियों ने रिहाई के बाद से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। उन्होंने जांच में सहयोग किया है और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों या संगठनों में उपस्थिति के आरोप मुकदमे में हस्तक्षेप के बराबर नहीं हैं।

(xviii) प्रतिवादी अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा के हकदार हैं। मशहूर हस्ती का दर्जा अलग-अलग जमानत मानकों का औचित्य नहीं ठहराता है। मीडिया की जांच और सार्वजनिक आक्रोश न्यायिक कार्यवाही में कानूनी साक्ष्यों की जगह नहीं ले सकते।

(xix) आरोप-पत्र दायर होने और जनवरी 2025 से अपील लंबित होने के बावजूद, कोई आरोप तय नहीं किए गए हैं और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। सार्थक प्रगति के बिना लंबे समय तक मुकदमे से पहले कारावास सजा से पहले सजा के खिलाफ संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है।

(xx) उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान अपीलें गलत समझी गई हैं, कानून में अस्थिर हैं, और प्रारंभिक चरण में ही खारिज किए जाने योग्य हैं। तथ्यों और बाध्यकारी मिसालों पर उचित विचार करने के बाद उच्च न्यायालय का दिनांक 13.12.2024 का आदेश, जिसमें प्रतिवादियों को नियमित जमानत दी गई थी, इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. हमने पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और हमारे सामने रखे गए दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

14. दिनांक 24.01.2025 को, जब इन मामलों पर विचार किया गया, तो इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर कोई दूसरा सह-आरोपी जमानत के लिए आवेदन करता है, तो संबंधित न्यायालय विवादित आदेश पर भरोसा नहीं करेगा। ऐसी किसी भी जमानत याचिका पर स्वतंत्र रूप से, उसके अपने गुणों के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए।

15. जमानत रद्द करने से जुड़ा कानूनी ढांचा अच्छी तरह से तय है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439(2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को ऐसे आरोपी को फिर से गिरफ्तार करने का निर्देश देने का अधिकार देती है जिसे जमानत पर रिहा किया गया है, अगर ऐसा निर्देश "आवश्यक" समझा जाता है। इसी तरह, धारा 437(5) एक न्यायिक दंडाधिकारी को धारा 437(1) या (2) के तहत दी गई जमानत को रद्द करने का अधिकार देती है। ये प्रावधान इस विधायी इरादे को रेखांकित करते हैं कि जमानत देने की शक्ति पूर्ण नहीं है, बल्कि उभरते तथ्यों या मूल आदेश में कानूनी त्रुटियों के आलोक में हमेशा न्यायिक पुनर्विचार के अधीन है।

16. यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि जमानत देने और उसे रद्द करने के लिए विचार समान नहीं होते हैं। जबकि जमानत देने में स्वतंत्रता के दुरुपयोग की संभावना का निवारक मूल्यांकन शामिल होता है, जमानत रद्द करने में पिछले फैसले की समीक्षा शामिल होती है- या तो बाद की परिस्थितियों के कारण या क्योंकि मूल आदेश कानूनी रूप से दोषपूर्ण था। जैसा कि **राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम संजय गांधी**[10] में कहा गया है, "जब जमानत के लिए आवेदन किया जाता है तो जमानत खारिज करना एक बात है; पहले से दी गई जमानत को रद्द करना बिल्कुल दूसरी बात है"। यह सिद्धांत एक बार दी गई स्वतंत्रता की पवित्रता की मान्यता और इसे वापस लेने के लिए ठोस औचित्य की आवश्यकता को दर्शाता है।

17. हालांकि, यह भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि प्रासंगिक कारकों - जैसे अपराध की गंभीरता, साक्ष्यों की ताकत, या आरोपी के आचरण और पूर्ववृत्त - पर उचित विचार किए बिना दी गई जमानत रद्द की जा सकती है। बाद में दुराचार की अनुपस्थिति में भी, एक जमानत आदेश जो विकृत, अनुचित, या कानूनी रूप से अस्थिर है, हस्तक्षेप के लिए कमजोर है। **दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य** (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने कहा कि "जहां जमानत आदेश महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करके या मनमाने तरीके से पारित किया जाता है, तो इसे रद्द किया जा सकता है"।

न्यायशास्त्र का परीक्षण करते हैं कि जमानत कब रद्द की जा सकती है। इस संबंध में दो अलग-अलग श्रेणियां सामने आई हैं:

(क) आदेश में कानूनी कमी के कारण जमानत का रद्द होना; और

(ख) जमानत रद्द करना, यानी, जमानत मिलने के बाद दुराचार या बाद की परिस्थितियों के कारण जमानत रद्द करना।

(क) जमानत आदेशों का रद्द होना

18.1. यह उस अपीलीय या पुनरीक्षण शक्ति से संबंधित है जिसके तहत किसी ऐसे जमानत आदेश को रद्द किया जा सकता है जो गलत, अनुचित हो, या स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करके पारित किया गया हो। यह बाद के आचरण पर ध्यान दिए बिना, जमानत दिए जाने के समय मौजूद त्रुटियों से संबंधित है।

18.2. **प्रहलाद सिंह भाटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**[11] में, इस न्यायालय ने मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए:

"(क) जमानत देते समय न्यायालय को न केवल आरोपों की प्रकृति, **बल्कि सजा की गंभीरता, यदि आरोप में दोषसिद्धि शामिल है और आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति को भी ध्यान में रखना होगा।**

(ख) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका पर भी जमानत देने के मामले में न्यायालय को विचार करना चाहिए।

(ग) हालांकि यह उम्मीद नहीं की जाती है कि आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने वाले सभी साक्ष्य हों, लेकिन आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि हमेशा होनी चाहिए।

(घ) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत देने के मामले में केवल वास्तविकता के तत्व पर ही विचार किया जाना चाहिए, और यदि अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह है, तो सामान्य परिस्थितियों में, आरोपी जमानत के आदेश का हकदार है।"

18.3. **पूरन बनाम रामबिलास और अन्य**[12] में, यह माना गया कि जमानत के बाद दुराचार की अनुपस्थिति में भी जमानत आदेश को रद्द किया जा सकता है यदि यह अनुचित, अवैध या गलत पाया जाता है।

18.4. इसी तरह, **डॉ. नरेंद्र के. अमीन बनाम गुजरात राज्य और अन्य**[13] में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि अप्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने से जमानत आदेश कमजोर हो जाता है और उसे रद्द किया जा सकता है।

18.5. **प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी**[14] में, इस न्यायालय ने माना कि जहां उच्च न्यायालय यांत्रिक रूप से और अपराध की गंभीरता या आरोपी के पिछले रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार किए बिना जमानत देता है, तो ऐसे आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

18.6. **प्रकाश कदम और अन्य बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता और अन्य**[15] के मामले में, इस न्यायालय ने उसी न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने और अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा रद्द करने के बीच अंतर बताया। न्यायालय ने कहा:

"18. यह तय करते समय कि जमानत रद्द की जाए या नहीं, न्यायालय को अपराध की गंभीरता और प्रकृति, आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला, आरोपी की स्थिति और हैसियत, आदि पर भी विचार करना होता है। यदि आरोपी के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है, भले ही उसने उसे दी गई जमानत का दुरुपयोग न किया हो। **इसके अलावा, उपरोक्त सिद्धांत तब लागू होता है जब उसी न्यायालय से जमानत रद्द करने के लिए संपर्क किया जाता है जिसने जमानत दी थी। यह तब लागू नहीं होगा जब जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ अपीलीय/पुनर्निरीक्षण न्यायालय में अपील की जाती है।**

19..... जमानत रद्द करने का निर्णय करते समय कई अन्य कारक भी देखे जा सकते हैं।"

18.7. **नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[16] के मामले में, इस न्यायालय ने एक जमानत आदेश को रद्द कर दिया, जहाँ उच्च न्यायालय ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को नज़रअंदाज़ कर दिया था और यांत्रिक रूप से समानता पर भरोसा किया था। इसने माना कि अप्रासंगिक कारकों पर विचार करना और प्रासंगिक विचारों को छोड़ देना आदेश को विकृत बनाता है। जैसा कि न्यायालय ने कहा:

"15. .... यह बिना बादल के आसमान की तरह साफ है कि उच्च न्यायालय ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है। उच्च न्यायालय ने समानता के सिद्धांत पर विचार किया है। एक आदतन अपराधी जो इस तरह के अपराधों में शामिल है, जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है, वे मामूली अपराध नहीं हैं कि उसे हिरासत में न रखा जाए, बल्कि अपराध जघन्य प्रकृति के हैं और ऐसे अपराधों को किसी भी तरह से तुच्छ नहीं माना जा सकता। ऐसे मामले एक विश्लेषणात्मक दिमाग में मूसलाधार बारिश के प्रभाव की क्षमता के साथ गरज और बिजली पैदा करते हैं। **कानून न्यायपालिका से उम्मीद करता है कि वह इस तरह के आरोपी व्यक्तियों को आज़ाद करते समय सतर्क रहे और इसलिए, विवेक का प्रयोग समझदारी से करने पर ज़ोर दिया जाता है, न कि मनमाने तरीके से।" इसे आगे स्पष्ट किया गया:**

"18. वाद खत्म करने से पहले, हम यह दोहराना चाहेंगे कि यह जमानत रद्द करने की अपील नहीं है, क्योंकि बाद में बदली हुई परिस्थितियों के कारण रद्द करने की मांग नहीं की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग इसलिए की गई है क्योंकि कई प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया गया है, जिसमें आरोपी का आपराधिक इतिहास शामिल है और यह आदेश को एक गलत आदेश बनाता है। इसलिए, इसका अनिवार्य परिणाम है कि विवादित आदेश को रद्द किया जाए।"

18.8. **अनिल कुमार यादव बनाम स्टेट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)**[17] में, इस न्यायालय ने दोहराया कि हालांकि कोई विस्तृत सूची नहीं बनाई जा सकती है, न्यायालयों को हमेशा सभी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, जिसमें अपराध की गंभीरता, प्रथम दृष्टया साक्ष्य , और विचारण में हस्तक्षेप की संभावना शामिल है।

18.9. **केरल राज्य बनाम महेश**[18] में, यह देखा गया कि अनुच्छेद 136 के तहत भी, जहां जमानत आदेशों में हस्तक्षेप दुर्लभ है, यह न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा यदि जमानत आदेश में सोच-समझकर काम न करने या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित पाया जाता है।

(ख) जमानत रद्द करना

18.10. हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों के अनुसार, जमानत देना आरोपी को पूरी तरह से आज़ाद नहीं करता है, बल्कि केवल हिरासत को राज्य से ज़मानतदारों को स्थानांतरित करता है। नतीजतन, जमानत रद्द करने में इस बात का मूल्यांकन शामिल है कि क्या आरोपी ने दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है।

18.11. **दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य** (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने जमानत रद्द करने को सही ठहराने वाले व्यापक, हालांकि विस्तृत नहीं, आधारों को रेखांकित किया, जिसमें शामिल हैं:

• न्याय की उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास;

• न्याय से बचना;

• जमानत की रियायत का दुरुपयोग;

• आरोपी के न्याय से भागने की संभावना।

18.12. **अब्दुल बासित बनाम अब्दुल कादिर चौधरी**[19] में, इस न्यायालय ने उन परिस्थितियों को विस्तार से बताया जिनमें धारा 439(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दी गई जमानत रद्द की जा सकती है, जिसमें शामिल हैं जहां आरोपी:

• जमानत के बाद इसी तरह की आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है;

• जांच में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है;

• साक्ष्यों से छेड़छाड़ करता है या गवाहों को प्रभावित करता है;

• गवाहों को डराता या धमकाता है;

• भागने या कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश करना;

• अनुपलब्ध हो जाना या छिप जाना;

• लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करना या ज़मानतदारों के नियंत्रण से बचना।

18.13. **महिपाल बनाम राजेश कुमार** (उपरोक्त) मामले में, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने समझाया:

"एक अपीलीय न्यायालय ज़मानत के आदेश को रद्द कर सकती है अगर यह पाया जाता है कि यह कानूनी सिद्धांतों के गलत इस्तेमाल पर आधारित है या जहां प्रासंगिक तथ्यों को नज़रअंदाज़ किया गया

है। दूसरी ओर, ज़मानत रद्द करना आमतौर पर ज़मानत मिलने के बाद के व्यवहार या बाद की परिस्थितियों से होता है।"

18.14. आखिर में, **दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[20] मामले में, इस न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि पहले से दी गई ज़मानत को सामान्य या यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए। केवल ठोस और बहुत ज़रूरी परिस्थितियां, जो मुकदमे की निष्पक्षता या न्याय के हित को खतरे में डालती हैं, ऐसे हस्तक्षेप को सही ठहराएंगी।

18.15. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि हालांकि जमानत रद्द करना एक गंभीर मामला है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होना शामिल है, कानून एक ऐसे जमानत आदेश को रद्द करने की अनुमति देता है जो अनुचित है, कानूनी रूप से अस्थिर है, या महत्वपूर्ण बातों पर उचित ध्यान दिए बिना पारित किया गया है। विकृति के कारण जमानत आदेशों को रद्द करने और जमानत के बाद दुराचार के लिए रद्द करने के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से

समझा और लागू किया जाना चाहिए, जिससे आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए एक सावधानीपूर्वक, सुनिश्चित और संवैधानिक रूप से सही दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।

19. इस प्रसंग पर, इस न्यायपीठ के **पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[21] के फैसले का उल्लेख करना उचित है, जिसमें, तथ्यों और अपराध की गंभीरता, अर्थात्, बाल तस्करी के साथ-साथ कानूनी सिद्धांतों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी गई थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक पोषित संवैधानिक मूल्य है, यह पूर्ण नहीं है। स्वतंत्रता को वहां झुकना होगा जहां यह समाज के सामूहिक हित के लिए खतरा पैदा करती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता जो दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता को खतरे में डालती है, क्योंकि तर्कसंगत समूह असामाजिक या सामूहिक विरोधी आचरण को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि जमानत न्यायशास्त्र स्वाभाविक रूप से तथ्य-विशिष्ट है, न्यायालय ने दोहराया कि प्रत्येक जमानत आवेदन पर उसके अपने गुणों के आधार पर, जमानत देने या अस्वीकार करने को नियंत्रित करने वाले अच्छी तरह से स्थापित मापदंडों के आलोक में अभिनिर्धारित लिया जाना चाहिए। अभिनिर्धारित के निम्नलिखित अनुच्छेद ग्राफ इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं:

"i. जमानत देने के लिए व्यापक सिद्धांत।

53. गुडिकांति नरसिम्हुलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, (1978) 1 एससीसी 240 में, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने, एक विचाराधीन व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की सामग्री पर विस्तार से बताते हुए, जमानत देते समय विचार किए जाने वाले प्रमुख कारकों को निर्धारित किया है, जिन्हें इस प्रकार उद्धृत किया गया है: -

"7. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरोप की प्रकृति महत्वपूर्ण कारक है और साक्ष्य की प्रकृति भी प्रासंगिक है। जिस सजा के लिए पक्षकार उत्तरदायी हो सकता है, यदि दोषी ठहराया जाता है या दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है, वह भी इस मुद्दे पर निर्भर करता है।

8. एक और ज़रूरी बात यह है कि क्या न्याय की प्रक्रिया को वह व्यक्ति बाधित करेगा जो कुछ समय के लिए आज़ाद होने के लिए न्यायालय के दयालु अधिकार क्षेत्र की मांग कर रहा है [पैट्रिक डेवलिन, द क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन इन इंग्लैंड (ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन 1960) पृ. 75 — मॉडर्न लॉ रिव्यू, खंड 81, जनवरी 1968, पृ. 54।]

9. इस प्रकार कानूनी सिद्धांत और अभ्यास इस बात को सही ठहराते हैं कि न्यायालय इस संभावना पर विचार करे कि आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है या अन्यथा न्याय की प्रक्रिया को दूषित कर सकता है। इस संदर्भ में, यह न केवल पारंपरिक है बल्कि तर्कसंगत भी है कि जमानत के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पिछले आचरण की जांच की जाए ताकि यह पता चल सके कि उसका आचरण खराब है या नहीं— खासकर ऐसा आचरण जो यह बताता हो कि जमानत पर रहते हुए उसके गंभीर अपराध करने की संभावना है। आदतन अपराधियों के संबंध में, यह अपराध विज्ञान के इतिहास का हिस्सा है कि एक बिना सोचे-समझे दिए गए जमानत के आदेश ने जमानत पाने वाले को समाज के सदस्यों पर और अपराध करने का अवसर दिया है। इसलिए, एक प्रतिवादी के आपराधिक आचरण के बारे में साक्ष्यों के आधार पर जमानत का विवेक, अप्रासंगिक नहीं है।"

(ज़ोर दिया गया)

54. प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एनसीटी, दिल्ली और अन्य, (2001) 4 एससीसी 280 में, इस न्यायालय ने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला कि जमानत मांगने वाले आवेदन से निपटते समय न्यायालयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे इस प्रकार निकाला जा सकता है:

“8. जमानत देने का अधिकार क्षेत्र प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग किया जाना चाहिए। जमानत देते समय, न्यायालय को ध्यान में रखना होगा आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति, सज़ा की गंभीरता जो दोषसिद्धि के बाद मिलेगी, आरोपी का चरित्र, व्यवहार, साधन और हैसियत, आरोपी से जुड़ी खास परिस्थितियाँ, विचारण में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता या राज्य के बड़े हित और इसी तरह के अन्य विचार। यह भी ध्यान में रखना होगा कि जमानत देने के उद्देश्य से विधायिका ने "साक्ष्य " के बजाय "विश्वास करने के लिए उचित आधार" शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि जमानत देने वाली न्यायालय केवल इस बात से संतुष्ट हो सकती है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई वास्तविक मामला है और क्या अभियोजन पक्ष आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य पेश कर पाएगा। [...]"

(ज़ोर दिया गया)

55. इस न्यायालय ने राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह मामले में, जिसका ज़िक्र (2002) 3 एससीसी 598 में है, न्यायमूर्ति बनर्जी के ज़रिए यह ज़ोर दिया कि जमानत के मामलों में विवेक का इस्तेमाल करते समय न्यायालय को इसे समझदारी से करना चाहिए। यह बताते हुए कि जमानत बिना किसी ठोस कारण के सामान्य तौर पर नहीं दी जानी चाहिए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही: -

“3. जमानत देना हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है- लेकिन, ऐसे विवेक का इस्तेमाल समझदारी से किया जाना चाहिए, न कि सामान्य तौर पर। बिना किसी ठोस कारण के जमानत का आदेश मान्य नहीं हो सकता। यह रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कि जमानत देना न्यायालय द्वारा निपटाए जा रहे मामले के संदर्भगत तथ्यों पर निर्भर करता है और तथ्य, हालांकि, हर मामले में अलग-अलग होते हैं। समाज में आरोपी की स्थिति पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में जमानत देने के मामले में मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता और इसे हमेशा अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो जमानत देने को सही ठहराती हैं। अपराध की प्रकृति जमानत देने के लिए बुनियादी विचारों में से एक है- अपराध जितना गंभीर होगा, जमानत खारिज होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, हालांकि, यह मामले के तथ्यात्मक मापदंड पर निर्भर करता है।”

(ज़ोर दिया गया)

56. कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन मामले में, जिसका ज़िक्र (2004) 7 एससीसी 528 में है, इस न्यायालय ने माना कि हालांकि यह स्थापित है कि जमानत याचिका पर विचार करने वाला न्यायालय साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों पर विस्तृत चर्चा नहीं कर सकता, फिर भी न्यायालय को जमानत देने को सही ठहराने वाले प्रथम दृष्टया कारणों का संकेत देना ज़रूरी है।

57. प्रसंता कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी मामले में, जिसका ज़िक्र (2010) 14 एससीसी 496 में है, इस न्यायालय ने देखा कि जहां उच्च न्यायालय ने यांत्रिक रूप से जमानत दी है, तो वह आदेश बिना सोचे-समझे दिए जाने के दोष से ग्रस्त होगा, जिससे वह अवैध हो जाएगा। इस न्यायालय ने उन परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित बातें कही जिनके तहत जमानत देने वाले आदेश को रद्द किया जा सकता है। ऐसा करते समय, जिन कारकों ने न्यायालय के जमानत देने के फैसले को गाइड किया होना चाहिए था, उन्हें भी नीचे विस्तार से बताया गया है:

"9. [...] यह सर्वविदित है कि यह न्यायालय, आमतौर पर, आरोपी को जमानत देने या खारिज करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि, यह उच्च न्यायालय का भी कर्तव्य है कि वह अपने विवेक का समझदारी से, सावधानी से और इस संबंध में इस न्यायालय के कई फैसलों में बताए गए बुनियादी सिद्धांतों के सख्त अनुपालन में इस्तेमाल करे। यह अच्छी तरह से तय है कि, अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक हैं:

(i) क्या यह मानने का कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि आरोपी ने अपराध किया था;

(ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(iii) दोषी ठहराए जाने की स्थिति में सजा की गंभीरता;

(iv) यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो आरोपी के भागने या फरार होने का खतरा;

(v) आरोपी का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और हैसियत;

(vi) अपराध के दोहराए जाने की संभावना;

(vii) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका; और

(viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय में बाधा पहुंचने का खतरा।"

(जोर दिया गया)

58. भूपेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2021) 17 एससीसी 220 में, इस न्यायालय ने यह तय करने के लिए अपीलीय शक्ति के प्रयोग के संबंध में टिप्पणियां कीं कि क्या जमानत वैध कारणों से दी गई है, जो जमानत रद्द करने के आवेदन से अलग है, यानी इस न्यायालय ने जमानत देने के एक विकृत आदेश को रद्द करने और जमानत रद्द करने के बीच अंतर किया, इस आधार पर कि आरोपी ने दुर्व्यवहार किया है या कुछ नए तथ्यों के कारण ऐसी रद्द करने की आवश्यकता है। महिपाल बनाम राजेश कुमार, (2020) 2 एससीसी 118 में संदर्भित किए गए मामले का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने नीचे दिए अनुसार कहा: -

"16. वे बातें जो जमानत देने के आदेश की सही होने की जांच करने में अपीलीय न्यायालय की शक्ति को निर्धारित करती हैं, वे जमानत रद्द करने का आवेदन की जांच से अलग होती हैं। जमानत देने के आदेश की सही होने की जांच इस आधार पर की जाती है कि क्या जमानत देने में विवेक का गलत या मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया गया था। जांच यह है कि क्या जमानत देने का आदेश गलत, गैर-कानूनी या अनुचित है। दूसरी ओर, जमानत रद्द करने का आवेदन की जांच आम तौर पर बाद की परिस्थितियों के मौजूद होने या जिस व्यक्ति को जमानत दी गई है, उसके द्वारा जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर की जाती है। [...]"

(जोर दिया गया)

59. आरोपी को ज़मानत देने वाले आदेश पर विचार करने और विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेने के पहलू पर इस न्यायालय के फैसलों में से एक है बृजमनी देवी बनाम पप्पू कुमार, जो (2022) 4 एससीसी 497 में संदर्भित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय की तीन-न्यायमूर्तियों की न्यायपीठ ने, आरोपी को ज़मानत देने वाले उच्च न्यायालय के एक बिना कारण और लापरवाही वाले आदेश [पप्पू कुमार बनाम बिहार राज्य, जो (2021) एससीसी अनलाइन पटना 2856 और पप्पू सिंह बनाम बिहार राज्य, जो (2021) एससीसी अनलाइन पटना 2857 में संदर्भित किया गया है] को रद्द करते हुए, निम्नलिखित बातें कही: -

"35. हालांकि हम इस बात से वाकिफ हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अनमोल अधिकार है, लेकिन साथ ही, ज़मानत के आवेदन पर विचार करते समय अदालतें आरोपी के खिलाफ लगाए गए

आरोपों की गंभीरता और मामले से जुड़े तथ्यों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकतीं, खासकर तब जब आरोप झूठे, तुच्छ या परेशान करने वाले न हों, बल्कि विवरण पर लाए गए पर्याप्त साक्ष्यों से समर्थित हों, ताकि न्यायालय पहली नज़र में किसी नतीजे पर पहुँच सके। ज़मानत देने के आवेदन पर विचार करते समय पहली नज़र का नतीजा कारणों से समर्थित होना चाहिए और विवरण पर लाए गए मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद ही उस पर पहुँचा जाना चाहिए। अपराध की प्रकृति, आरोपी के आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, और आरोपी के खिलाफ लगाए गए अपराधों के संबंध में सज़ा की प्रकृति जैसे तथ्यों पर उचित विचार किया जाना चाहिए।"

(ज़ोर दिया गया)

60. मनोज कुमार खोखर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (2022) 3 एससीसी 501 में, माननीय न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने न्यायपीठ की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

"37. आखिरकार, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय को विवेकपूर्ण तरीके से और कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, एक ओर आरोपी द्वारा किए गए कथित अपराध को ध्यान में रखते हुए और दूसरी ओर मामले की सुनवाई की निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए, अपने विवेक का प्रयोग करना होता है।

38. इस प्रकार, हालांकि जमानत देने के लिए विस्तृत कारण नहीं बताए जा सकते हैं या जमानत याचिका पर विचार करने वाले न्यायालय द्वारा मामले के गुणों पर व्यापक चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन बिना किसी तर्क या प्रासंगिक कारणों के बिना कोई आदेश जमानत नहीं दे सकता है। ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष या suchak को उच्च मंच के समक्ष आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। जैसा कि गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1978) 1 एससीसी 118: 1978 एससीसी (क्रिमिनल) 41 : 1978 क्रिमिनल ला जर्नल 129] में उल्लेख किया गया है, जब किसी आरोपी को जमानत दी गई है, तो राज्य, यदि ऐसी जमानत दिए जाने के बाद नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो धारा 439(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है। हालांकि, यदि जमानत दिए जाने के बाद से कोई नई परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं, तो राज्य जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ अपील कर

सकता है, इस आधार पर कि यह विकृत या अवैध है या उन महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज करके दिया गया है जो आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करते हैं।"

(ज़ोर दिया गया)

61. हमने ऊपर बताए गए न्यायिक-निर्णयों का ज़िक्र सिर्फ़ दो वैचारिक सिद्धांतों को दोहराने के लिए किया है, यानी, जब अपराध गंभीर प्रकृति के हों तो आरोपी को ज़मानत देते समय किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए, और बाद में पैदा हुई परिस्थितियों के कारण ज़मानत रद्द करने और अपील में ज़मानत देने वाले आदेश को रद्द करने के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के बीच का अंतर, जब ज़मानत आदेश को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि वह गलत है या अप्रासंगिक बातों पर आधारित है या उन बातों पर विचार न करने पर आधारित है जो प्रासंगिक हैं।

62. हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ हल्के में पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने का उसके मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जेल जाने से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कमी आ जाती है। कभी-कभी इससे खालीपन का एहसास होता है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक सभ्य समाज में स्वतंत्रता की पवित्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कानून के शासन से बंधी है, एक व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह कानून द्वारा तय सामाजिक पाबंदियों के दायरे में रहकर आगे बढ़े। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बड़े सामाजिक हित से सीमित होती है और इसे छीनने के लिए कानून की सही स्वीकार्यता होनी चाहिए। एक व्यवस्थित समाज में एक व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह गरिमा के साथ रहे, कानून का सम्मान करे और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करे। यह एक माना हुआ सिद्धांत है कि स्वतंत्रता की अवधारणा निरंकुशता के दायरे में नहीं है, बल्कि सीमित है। न्याय के लिए सामूहिक आवाज़, शांति और सद्भाव की उनकी इच्छा और सुरक्षा की उनकी ज़रूरत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कानून के शासन वाले समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित किया जाना चाहिए और ऐसे नियम जो कानून का स्रोत हैं, सामाजिक संतुलन बनाए रखते हैं और मानवाधिकारों की सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मूल रूप से, कानून उनके पालन के लिए बनाए जाते हैं ताकि समाज का हर सदस्य समाज में शांति से रहे और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक हितों को प्राप्त कर सके। इसीलिए एडमंड बर्क ने स्वतंत्रता पर चर्चा करते हुए कहा था, "यह नियंत्रित स्वतंत्रता है"।

63. यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता या इतनी ऊँची जगह पर नहीं रखा जा सकता जिससे समाज में अराजकता या अव्यवस्था फैल जाए। बड़े न्याय की संभावना के लिए ज़रूरी है कि एक सभ्य माहौल में कानून और व्यवस्था बनी रहे। यह सच है कि मापदंडों को सटीक रूप से तय करने के लिए कोई गणितीय सूत्र नहीं हो सकता, लेकिन न्याय में न केवल सोच-समझकर काम करना चाहिए, बल्कि स्वीकृत और स्थापित मानदंडों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग भी करना चाहिए। एक समाज में कानून और व्यवस्था स्थापित सिद्धांतों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि संक्रामक अपराध महामारी न बन जाएं। एक संगठित समाज में स्वतंत्रता की अवधारणा के लिए मूल रूप से नागरिकों को ज़िम्मेदार होना चाहिए और उस शांति और सुरक्षा को भंग नहीं करना चाहिए जो हर नेक इंसान चाहता है। जे. ओर्टर ने यूं ही नहीं कहा था: "व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून की सीमाओं के भीतर बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करने का अधिकार है।"

64. इस तरह विश्लेषण करने पर यह साफ़ है कि हालांकि स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही कीमती मूल्य है, लेकिन यह एक नियंत्रित और सीमित स्वतंत्रता है और समाज का कोई भी तत्व इस तरह से काम नहीं कर सकता जिसके परिणामस्वरूप दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो, क्योंकि समझदार समाज किसी भी असामाजिक या समाज विरोधी काम को बर्दाश्त नहीं करता है। [देखें: ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, संदर्भित (2012) 9 एससीसी 446]।

छ. निष्कर्ष

67. अपराध की गंभीर प्रकृति और आरोपियों द्वारा अपनाए गए तरीके को देखते हुए, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय को आरोपियों के पक्ष में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि उच्च न्यायालय ने सभी जमानत आवेदनों को बहुत ही लापरवाही से निपटाया। उच्च न्यायालय के इस लापरवाह रवैये का नतीजा यह हुआ कि कई आरोपी फरार हो गए और इस तरह विचारण खतरे में पड़ गया।

72. आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक भी सामाजिक हित की रक्षा के लिए स्वतंत्रता पर कुछ सीमाओं का समर्थन करते हैं और स्वतंत्रता और प्रतिबंध के बीच आनुपातिकता का समर्थन करते हैं, इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित शब्दों में अपवाद बताते हैं:

"मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता के लिए ठीक उसी अनुपात में योग्य होते हैं जिस अनुपात में वे अपनी इच्छाओं पर नैतिक लगाम लगाते हैं, जिस अनुपात में न्याय के प्रति उनका प्रेम उनकी लालच से ऊपर होता है, जिस अनुपात में उनकी समझदारी और संयम उनकी घमंड और अहंकार से ऊपर होता है, जिस अनुपात में वे धूर्तों की चापलूसी के बजाय बुद्धिमान और अच्छे लोगों की सलाह सुनने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। समाज तब तक मौजूद नहीं रह सकता, जब तक इच्छा और भूख पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति कहीं न कहीं न हो; और जितना कम यह अंदर होगा, उतना ही अधिक यह बाहर होना चाहिए। यह चीजों के शाश्वत संविधान में तय है, कि असंयमित मन वाले लोग आज़ाद नहीं हो सकते। उनके जुनून ही उनकी बेड़ियाँ गढ़ते हैं।"

(जोर दिया गया)

73. इस प्रकार, राज्य या अन्य ऐसी मानवीय अभिकरण द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रयोग पर कुछ प्रतिबंध या सीमाएँ, एक सुव्यवस्थित समाज की स्वतंत्रता या सामाजिक हित के लिए आवश्यक तत्व हैं।

74. इस न्यायालय ने यह भी माना है कि असीमित और बिना शर्त स्वतंत्रता को सामाजिक हित में नहीं कहा जा सकता। करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1994) 3 एससीसी 569 में रिपोर्ट किए गए मामले में, इस न्यायालय ने कहा:

"स्वतंत्रता अकेली नहीं रह सकती बल्कि इसे साथी गुणों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, यानी गुण और नैतिकता, स्वतंत्रता और कानून, स्वतंत्रता और न्याय, स्वतंत्रता और आम भलाई, स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी जो व्यवस्थित प्रगति और सामाजिक स्थिरता के लिए ज़रूरी हैं।

इंसान एक तर्कसंगत व्यक्ति होने के नाते उसे दूसरों के समान अधिकारों के साथ तालमेल बिठाकर रहना होता है और अलग-अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए और भी अलग तरह से। यह आपस में जुड़ा हुआ जाल आचरण के परिभाषित क्षेत्रों के भीतर सीमांकित करना मुश्किल है जिसके भीतर कार्रवाई की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। इसलिए, स्वतंत्रता हमेशा पूर्ण अनुज्ञा नहीं होगी बल्कि इसे कानून की सीमाओं के भीतर खुद को मज़बूत करना होगा। दूसरे शब्दों में, सामाजिक प्रतिबंध के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इसलिए, स्वतंत्रता, एक सामाजिक अवधारणा के रूप में समाज के सभी सदस्यों को सुनिश्चित किया जाने वाला अधिकार है। जब तक समाज के सभी सदस्यों पर प्रतिबंध लागू नहीं किया जाता और वे इसे स्वीकार नहीं करते, कुछ लोगों की स्वतंत्रता में दूसरों का उत्पीड़न शामिल होगा। यदि स्वतंत्रता को एक सामाजिक व्यवस्था माना जाता है, तो स्वतंत्रता स्थापित करने की समस्या

प्रतिबंध को व्यवस्थित करने की समस्या होनी चाहिए जिसे समाज व्यक्ति पर नियंत्रित करता है। इसलिए, प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता सबसे बड़ी संख्या की स्वतंत्रता से पैदा होती है और उसके अधीन होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में समाज के लक्ष्य के रूप में आम खुशी, ऐसा न हो कि अराजकता और अव्यवस्था सामाजिक कल्याण और सद्भाव को नुकसान पहुंचाए और शक्तिशाली ताकतें सामाजिक कल्याण और व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए काम करें। इस प्रकार नागरिक स्वतंत्रता का सार सामाजिक नियंत्रण की सीमा के अधीन व्यक्ति की स्वतंत्रता को जीवित रखना है जिसे गतिशील सामाजिक विकास की ज़रूरतों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।"

(ज़ोर दिया गया)

75. गुडिकांति नरसिम्हुलु (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:-

"आखिरकार, किसी आरोपी या दोषी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक है, जो केवल 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के संदर्भ में ही कानूनी रूप से सीमित हो सकती है। अनुच्छेद 21 के अंतिम चार शब्द उस मानवाधिकार की जान हैं। पुलिस शक्ति का सिद्धांत सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता और आम जनता के हित को बनाए रखने के लिए दंडात्मक प्रक्रियाओं को संवैधानिक रूप से मान्य करता है। फिर भी, इसमें शामिल गंभीर मुद्दे को देखते हुए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना, चाहे वह क्षणिक हो या स्थायी, समाज के कल्याण उद्देश्यों से संबंधित सबसे गंभीर विचारों पर आधारित होना चाहिए, जैसा कि संविधान में निर्दिष्ट है।"

(ज़ोर दिया गया)

76. किसी भी परिस्थिति में, उच्च न्यायालय संतोषसाव , जगवीर बरनवाल और मनीष जैन को क्रमशः जमानत पर रिहा नहीं कर सकता था।

77. ऊपर बताई गई परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि हमें उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने वाले सभी आदेशों को रद्द कर देना चाहिए और उन्हें विचारण न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाना चाहिए।

78. अंतिम बात: यह पता लगाने का असली तरीका कि विवेक का इस्तेमाल समझदारी से किया गया है या नहीं, यह देखना है कि क्या न्यायालय आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के हित, दूसरे शब्दों में, सामाजिक हितों के बीच संतुलन बनाने में सक्षम रहा है। प्रत्येक जमानत याचिका पर मामले

के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए जो जमानत देने या इनकार करने के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों से संबंधित हैं। फिलिप स्टैनहोप के शब्दों में, "हर मौके पर फैसले की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन विवेक की हमेशा ज़रूरत होती है"।

79. नतीजतन, ये सभी अपीलें सफल होती हैं और स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत के विवादित आदेशों को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।"

20. इस मामले में, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा, मुख्य रूप से कुछ तथ्यात्मक और कानूनी निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादियों को जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि, इन निष्कर्षों की बारीकी से जांच करने पर गंभीर कमियां सामने आती हैं, जिनमें दखल देने की ज़रूरत है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

20.1. **गिरफ्तारी के आधार पर प्रस्तुत करने में देरी, अपने आप में, जमानत देने के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकती है।**

20.1.1. प्रतिवादियों – आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि गिरफ्तारी के आधार तुरंत लिखित में नहीं दिए गए थे, जिससे संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और धारा 50 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 का उल्लंघन हुआ। हालांकि, यह दलील बेबुनियाद है।

20.1.2. संविधान का अनुच्छेद 22(1) यह अनिवार्य करता है कि "गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को, जितनी जल्दी हो सके, गिरफ्तारी के कारणों की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, और न ही उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा"। इसी तरह, धारा 50 (1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता इसमें कहा गया है कि "हर पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को

बिना वारंट के गिरफ्तार करता है, वह तुरंत उसे उस अपराध की पूरी जानकारी देगा जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है या गिरफ्तारी के अन्य आधार बताएगा।

20.1.3. इस प्रकार संवैधानिक और कानूनी ढांचा यह अनिवार्य करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए – लेकिन कोई भी प्रावधान कोई विशिष्ट रूप

निर्धारित नहीं करता है या हर मामले में लिखित संचार पर जोर नहीं देता है। न्यायिक मिसालों ने स्पष्ट किया है कि इन आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त है, जब तक कि स्पष्ट नुकसान न दिखाया जाए।

20.1.4. **विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य**[22] में, यह दोहराया गया कि अनुच्छेद 22(1) तब संतुष्ट होता है जब आरोपी को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सार रूप में अवगत कराया जाता है, भले ही लिखित रूप में न बताया गया हो। इसी तरह, **कासिरेड्डी उपेंद्र रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[23] में, यह देखा गया कि जब गिरफ्तारी वारंट के अनुसार की जाती है, तो वारंट पढ़कर सुनाना पर्याप्त अनुपालन माना जाता है। पंकज बंसल के बाद के ये दोनों फैसले स्पष्ट करते हैं कि लिखित, व्यक्तिगत आधार सभी परिस्थितियों में एक अपरिवर्तनीय आवश्यकता नहीं हैं।

20.1.5. जबकि धारा 50, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की भावना का पालन अनिवार्य है, लगातार न्यायिक दृष्टिकोण कथित प्रक्रियात्मक चूकों की जांच करते समय पूर्वाग्रह उन्मुख परीक्षण अपनाने का रहा है। केवल लिखित आधारों की अनुपस्थिति अपने आप गिरफ्तारी को अवैध नहीं बनाती है, जब तक कि इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट नुकसान या बचाव का उचित अवसर न मिले।

20.1.6. हालांकि, उच्च न्यायालय ने कथित प्रक्रियात्मक चूक पर एक निर्णायक कारक के रूप में बहुत अधिक भरोसा किया, जबकि धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध की गंभीरता और प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। इसने, अन्य बातों के अलावा, यह नोट किया कि रिमांड आदेशों में गिरफ्तारी के आधारों के ज्ञापन की तामील के बारे में कोई उल्लेख नहीं था (अनुच्छेद 45); गिरफ्तारी ज्ञापन कथित तौर पर नमूना प्रपत्रों पर आधारित थे और व्यक्तिगत नहीं थे (अनुच्छेद 50); और चश्मदीदों ने यह नहीं कहा था कि वे गिरफ्तारी के समय मौजूद थे या उन्होंने ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे (अनुच्छेद 48)। **पंकज बंसल बनाम भारतीय संघ**[24] और **प्रबीर पुरकायस्थ बनाम स्टेट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)** (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए, इसने निष्कर्ष निकाला (अनुच्छेद 43, 49 – 50) कि 03.10.2023 से, गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तारी के विस्तृत, लिखित,

और व्यक्तिगत आधारों को न बताना एक उल्लंघन था जो आरोपी को जमानत का हकदार बनाता था।

20.1.7. इस मामले में, गिरफ्तारी ज्ञापन और रिमांड विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रतिवादियों को उनकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी थी। उन्हें शुरू से ही कानूनी प्रतिनिधित्व मिला हुआ था और उन्होंने गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत के लिए आवेदन किया, जो आरोपों की तत्काल और सूचित

समझ को दर्शाता है। यह स्थापित करने के लिए विवरण पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि कथित प्रक्रियात्मक चूक के कारण कोई पूर्वाग्रह हुआ था। प्रदर्शन योग्य पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति में, ऐसी अनियमितता, सबसे अच्छी स्थिति में, एक ठीक करने योग्य दोष है और अपने आप में, जमानत पर रिहाई की गारंटी नहीं दे सकती। जैसा कि ऊपर दोहराया गया है, उच्च न्यायालय ने इसे एक निर्णायक कारक माना जबकि धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप की गंभीरता और प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। पंकज बंसल और प्रबीर पुरकायस्थ पर इसका भरोसा गलत है, क्योंकि वे अभिनिर्धारित भौतिक रूप से अलग तथ्यों और वैधानिक संदर्भों पर आधारित थे। यहां अपनाया गया दृष्टिकोण इस स्थापित सिद्धांत के साथ असंगत है कि गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने में प्रक्रियात्मक चूक, पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति में, अपने आप हिरासत को अवैध नहीं बनाती है या आरोपी को जमानत का हकदार नहीं बनाती है।

20.2**. न्यायालयों से जमानत के चरण में मामले के गुणों पर निष्कर्ष देने की उम्मीद नहीं की जाती है।**

20.2.1. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जमानत के चरण में, न्यायालयों को साक्ष्यों की विस्तृत जांच करने या ऐसे निष्कर्ष देने से रोका जाता है जो मामले के गुणों को प्रभावित करते हैं। केवल सामग्री का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन ही उचित है। न्यायालय एक लघु-विचारण नहीं कर सकती है या ऐसे निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकती है जो विचारण के परिणाम को प्रभावित कर सकें।

20.2.2. **निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे**[25] में, इस न्यायालय ने जैसा कि नीचे कहा गया है:

"जमानत याचिका पर आदेश देते समय साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों का विस्तृत विश्लेषण करने से बचना चाहिए। पहली नज़र में मामला सही है, इस बात से संतुष्ट होना ज़रूरी है, लेकिन यह आदेश में ही मामले की खूबियों की पूरी जांच करने जैसा नहीं है।"

20.2.3. **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन @ पप्पू यादव**[26] में, न्यायालय ने दोहराया कि हालांकि विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जमानत देने के लिए कुछ तर्क होने चाहिए, खासकर जब अपराध गंभीर हो। हालांकि, ऐसे मामलों में भी, तर्क प्रथम दृष्टया संतुष्टि तक ही सीमित होना चाहिए, न कि गुण-दोष -आधारित निष्कर्षों तक।

20.2.4. विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मामले की गुण-दोष में जाकर और ऐसे निष्कर्ष दर्ज करके आरोपी को जमानत दे दी, जो विचारण न्यायालय के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 24 में, उच्च न्यायालय ने देखा कि इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति से मृतक पर हमला करने और हत्या करने की पूर्वयोजना का संकेत नहीं मिलता है, और निष्कर्ष निकाला कि हत्या करने के इरादे का निर्धारण विचारण के दौरान किया जाना होगा। उसी अनुच्छेद में, उसने आगे कहा कि चूंकि मृतक स्वेच्छा से कुछ आरोपियों के साथ बेंगलुरु गया था और रास्ते में एक बार में भी रुका था, इसलिए यह सवाल कि उसका अपहरण किया गया था या नहीं, इसके लिए भी पूर्ण विचारण की आवश्यकता है। अनुच्छेद 29 में, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया कोई सामग्री नहीं थी जो साजिश का खुलासा करती हो क्योंकि किसी भी गवाह के बयान ने अभियोजन पक्ष के पूर्व नियोजित हत्या के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। अनुच्छेद 32 में, उच्च न्यायालय ने हथियारों की बरामदगी के साक्ष्य मूल्य को सिर्फ इसलिए कम कर दिया क्योंकि उन्हें एक खुली जगह से जब्त किया गया था। चिकित्सा साक्ष्य के संबंध में, अनुच्छेद 31 में न्यायालय ने पाया कि डॉक्टर द्वारा बाद में जारी की गई एक और राय (जिसमें कहा गया था कि 39 चोटों में से 13 से खून बह रहा था) पोस्टमार्टम विवरण के विपरीत थी, और कहा कि इस विसंगति का मूल्यांकन विचारण में किया जाना चाहिए। ये अपराध या निर्दोषता के समय से पहले न्यायिक मूल्यांकन के संकेत हैं, जो जमानत के चरण में अस्वीकार्य है।

20.2.5. इसके अलावा, उच्च न्यायालय का ऐसा रवैया इस न्यायालय के न्यायिक मिसालों के विपरीत है, जिसमें **सतीश जग्गी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[27], कंवर सिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य[28]**, शामिल हैं, जिसमें यह माना गया था कि न्यायालय, जमानत पर विचार करते समय, गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन नहीं करेंगे, क्योंकि यह कार्य पूरी तरह से विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का विवादित आदेश गवाहों के बयानों में देरी पर टिप्पणी करके और इस स्तर पर विश्वसनीयता की कमी का आरोप लगाकर इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

20.2.6. **बृजमनी देवी बनाम पप्पू कुमार[29]** में, न्यायालय ने चेतावनी दी कि जमानत देने के आवेदन पर आदेश पारित करते समय, ऐसे विस्तृत विवरण दर्ज नहीं किए जा सकते हैं जिससे यह आभास हो कि मामला ऐसा है जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होगी या, इसके विपरीत, बरी किया जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेद ग्राफ प्रासंगिक हैं:

"25. हालांकि हम इस बात से वाकिफ हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अनमोल अधिकार है, फिर भी जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय अदालतें आरोपी के खिलाफ लगाए गए

आरोपों की गंभीरता और मामले से जुड़े तथ्यों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकतीं, खासकर तब जब आरोप झूठे, तुच्छ या परेशान करने वाले न हों, बल्कि विवरण पर लाए गए पर्याप्त साक्ष्यों से समर्थित हों, ताकि न्यायालय पहली नज़र में किसी नतीजे पर पहुँच सके। जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय पहली नज़र में निकाला गया निष्कर्ष कारणों से समर्थित होना चाहिए और मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद ही उस पर पहुँचा जाना चाहिए। अपराध की प्रकृति, यदि कोई हो तो आरोपी के आपराधिक इतिहास, और आरोपी के खिलाफ लगाए गए अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि के बाद मिलने वाली सज़ा की प्रकृति जैसे तथ्यों पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

26. हमने ऊपर विवादित आदेशों के प्रासंगिक हिस्सों को निकाला है। शुरू में, हम देखते हैं कि निकाले गए हिस्से ही उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देते समय "तर्क" का हिस्सा हैं। जैसा कि ऊपर बताए गए फैसलों से पता चलता है, न्यायालय के लिए जमानत देते समय विस्तृत कारण देना ज़रूरी नहीं है, खासकर जब मामला शुरुआती चरण में हो और आरोपी द्वारा किए गए अपराधों के आरोप अभी तक स्पष्ट न हुए हों। **जमानत देने के आवेदन पर आदेश पारित करते समय यह आभास देने के लिए विस्तृत विवरण दर्ज नहीं किया जा सकता कि मामला ऐसा है जिससे दोषसिद्धि होगी या, इसके विपरीत, बरी हो जाएगा।** साथ ही, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति; यदि आरोप उचित संदेह से परे साबित होते हैं और दोषसिद्धि होती है तो सज़ा की गंभीरता; आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने का उचित डर; साक्ष्यों से छेड़छाड़; अभियोजन पक्ष के मामले में तुच्छता; आपराधिक इतिहास के बीच संतुलन बनाना होगा। आरोपी का; और आरोपी के खिलाफ आरोप के समर्थन में न्यायालय की पहली नज़र में संतुष्टि।"

20.2.7. मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ने से यह साफ़ पता चलता है कि उसने विचारण के नतीजे का पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया है, जिससे बरी होने या दोषमुक्ति का रास्ता साफ़ हो गया है, जो इस न्यायालय के अनुसार, कानून के खिलाफ है।

20.2.8. **दिनेश एम.एन. (एसपी) बनाम गुजरात राज्य**[30] में, न्यायालय ने साफ़ किया:

“भले ही जमानत देने वाले न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्यों के दोबारा मूल्यांकन से बचना चाहिए, लेकिन धारा 439(2) के तहत जमानत रद्द करने की अर्जी पर विचार करने वाला न्यायालय यह देख

सकता है कि क्या गैर-ज़रूरी चीज़ों पर विचार किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पता नहीं है कि जमानत की अर्जी स्वीकार करते समय गैर-ज़रूरी चीज़ों का न्यायालय पर कितना असर पड़ा।"

20.2.9. इस तरह, इस न्यायालय ने यह साफ़ कर दिया है कि जमानत पर निर्णय करते समय उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को केवल उसी मकसद के लिए राय की अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए और किसी भी तरह से विचारण या अन्य कार्यवाही पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि, मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय ने गैर-ज़रूरी और समय से पहले के आकलन पर भरोसा किया है, और ऐसे सवालों में दखल दिया है जिन्हें विचारण के लिए छोड़ देना चाहिए था, जिससे एक गंभीर क्षेत्राधिकार संबंधी गलती हुई है।

20.3. जमानत के चरण में साक्ष्यों का मूल्यांकन अस्वीकार्य है।

20.3.1. **उड़ीसा राज्य बनाम महिमानंद मिश्रा**[31] में, माननीय न्यायालय ने कहा:

"11. यह आम जानकारी है कि आम तौर पर साज़िश को साबित करने के लिए सीधे साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि साज़िश का काम गुप्त रूप से होता है। केवल साज़िश करने वालों को ही साज़िश के बारे में पता होगा। हालांकि, न्यायालय, साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय, अन्य साक्ष्यों पर भरोसा कर सकता है जो साज़िश का संकेत देते हैं। ऐसे साक्ष्य विचारण के दौरान रिकॉर्ड पर होंगे। हालांकि, इस स्तर पर, पहली नज़र में, न्यायालय को ज़मानत की अर्ज़ी पर विचार करते समय समग्र साक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा।

12. हालांकि यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय के आरोपी को ज़मानत देने या खारिज करने के आदेशों में दखल नहीं देगा, लेकिन इस न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करना संभव है, जहां यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने अपने विवेक का इस्तेमाल समझदारी से और ज़मानत देने के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि ज़मानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को कुछ कारकों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि आरोपी के खिलाफ पहली नज़र में मामला होने का अस्तित्व, आरोपों की गंभीरता, आरोपी की स्थिति और दर्जा, आरोपी के न्याय से भागने और अपराध दोहराने की संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और न्यायालयों को बाधित करने की संभावना साथ ही आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड। यह भी अच्छी तरह से तय हो गया है कि न्यायालय को ज़मानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय मामले

की खूबियों में गहराई से नहीं जाना चाहिए। विवरण से बस इतना ही स्थापित करने की ज़रूरत है कि आरोपी के खिलाफ पहली नज़र में मामला मौजूद है।"

20.3.2. **नरेश कुमार मंगला बनाम अनीता अग्रवाल**[32] में, इस न्यायालय ने आरोप-पत्र और आरोपी के खिलाफ पहली नज़र में प्रतिकूल पाए गए साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपी को दी गई अग्रिम ज़मानत रद्द कर दी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ज़मानत के स्तर पर साक्ष्यों की जांच विचारण को प्रभावित नहीं करेगी।

20.3.3. **ईश्वरजी नागाजी माली बनाम गुजरात राज्य और अन्य**[33] के मामले में, न्यायालय ने आरोप-पत्र के साक्ष्यों की जांच की और माना कि पहली नज़र में पर्याप्त साक्ष्य थे, जिन्हें उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय नज़रअंदाज़ कर दिया था, और इसलिए जमानत आदेश को रद्द कर दिया। (इस मामले पर नीचे एक और प्रस्ताव के लिए विस्तार से चर्चा की गई है)।

20.3.4. **इमरान बनाम मोहम्मद भावा**[34] में, तीन-जजों की न्यायालयपीठ ने निम्नलिखित निर्णय सुनाया:

"32. इस न्यायालय ने नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में दोहराया है कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कुछ कारकों पर विचार करे और वे मूल रूप से हैं, (i) आरोप की प्रकृति और दोषी पाए जाने पर सज़ा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, (ii) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका, और (iii) आरोप के समर्थन में न्यायालय की पहली नज़र में संतुष्टि।"

33. ऊपर बताए गए इस न्यायालय के फैसलों के अनुपात को हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि उच्च न्यायालय ने जमानत देने के लिए बुनियादी सिद्धांतों पर विचार न करके गलती की, जो विभिन्न न्यायिक फैसलों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित हैं। उच्च न्यायालय इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर गया कि आरोपी प्रतिवादियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, ताकि उनके खिलाफ पहली नज़र में मामला स्थापित किया जा सके।"

20.3.5. **प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता** (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि दुरुपयोग के बिना भी, गंभीर आरोपों के लिए जमानत रद्द की जा सकती है यदि निचली न्यायालय ने साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ किया हो।

20.3.6. मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय ने कुछ अभियोजन गवाहों और फोरेंसिक सामग्री की विश्वसनीयता का विश्लेषण करने और उसे कम आंकने का भी काम किया। इसने आरोपी के खुले कृत्यों के संबंध में चश्मदीद गवाहों के बयानों में विरोधाभास देखा (अनुच्छेद 26)।

इसने न्यायालय गवाह संख्या 76 और न्यायालय गवाह संख्या 91 के बयान दर्ज करने में देरी के बारे में अभियोजन पक्ष की व्याख्या पर संदेह व्यक्त किया (अनुच्छेद 27)। इसने डॉक्टर की पूरक राय के समय पर सवाल उठाया और उसके साक्ष्य मूल्य का मूल्यांकन किया (अनुच्छेद 31)। जैसा कि पहले ही बताया गया है, गवाहों की विश्वसनीयता या भरोसेमंदता पूरी तरह से जिरह के बाद विचारण न्यायालय द्वारा तय करने का मामला है। यह एक स्थापित कानून है कि धारा 161, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान ठोस नहीं होते हैं, और उनका साक्ष्य मूल्य केवल विचारण के दौरान जिरह के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। जमानत के चरण में दी गई कोई भी राय विचारण के परिणाम का पहले से अनुमान लगाने का जोखिम उठाती है और इससे बचा जाना चाहिए। इस प्रकार, इन पहलुओं पर न्यायालय का मूल्यांकन अभियोजन साक्ष्य के प्रमाणिक मूल्य का समय से पहले मूल्यांकन करने के बराबर है।

20.4. **आरोप-पत्र दाखिल करना या गवाहों की लंबी सूची जमानत देने का आधार नहीं है।**

20.4.1. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि केवल आरोप-पत्र दाखिल करने से जमानत का एक अकाट्य अधिकार नहीं मिलता है। इसी तरह, केवल लंबे विचारण की संभावना अपने आप में अपराध की गंभीरता, जांच के दौरान इकट्ठा की गई दोषी सामग्री, या गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से अधिक नहीं हो सकती है।

20.4.2. **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि:

"उच्च न्यायालय सिर्फ **विचारण खत्म होने में देरी के आधार पर जमानत याचिका स्वीकार नहीं कर सकता था, बिना अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर विचार किए, जैसे कि प्रथम दृष्टया मामले का अस्तित्व, अपराध की गंभीरता, और जमानत पर रहते हुए धमकी और प्रलोभन देकर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप।** ... इन पर विचार न करना और सिर्फ लंबी कैद के आधार पर जमानत देना, आदेश को अमान्य कर देता है..."

20.4.3. **बृजमनी देवी बनाम पप्पू कुमार** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि आरोपी के भागने या गवाहों को धमकाने की संभावना का विचारण की निष्पक्षता पर सीधा असर पड़ता है। गंभीर अपराधों में, ऐसी आशंकाएं – जब विवरण द्वारा उचित रूप से समर्थित हों – तो जमानत देने के खिलाफ होनी चाहिए।

20.4.4. इसी तरह, **ईश्वरजी नागाजी माली बनाम गुजरात राज्य** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने दोहराया कि यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कोई वैध आधार नहीं है, खासकर

जहां जांच के दौरान परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला प्रथम दृष्टया स्थापित हो गई हो। न्यायालय ने उस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि:

"6. .... उच्च न्यायालय ने अनुसंधान के दौरान इकट्ठा किए गए साक्ष्यों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। उच्च न्यायालय ने अनुसंधान के दौरान इकट्ठा किए गए साक्ष्यों/सामग्री पर पहली नज़र में भी विचार नहीं किया और उसने प्रतिवादी संख्या 2 को इतने गंभीर अपराध में, जिसमें उसने अपनी पत्नी को मारने की साज़िश रची थी, सिर्फ़ यह कहकर रिहा करने का निर्देश दिया कि क्योंकि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का मामला है, जो कि एक कमज़ोर साक्ष्य है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत देने से इनकार करना कानूनी और सही नहीं है। **सिर्फ़ इसलिए कि अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, यह आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता, अगर अनुसंधान के दौरान साक्ष्य /सामग्री इकट्ठा किए गए हैं और पहली नज़र में घटनाओं की पूरी कड़ी स्थापित हो जाती है।** जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय, उच्च न्यायालय के माननीयएकल न्यायमूर्ति ने अनुसंधान के दौरान इकट्ठा किए गए किसी भी साक्ष्य/सामग्री पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और/या विचार नहीं किया, जो आरोप-पत्र का हिस्सा है।

7. प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक और कारण यह है कि आरोपी की समाज में गहरी जड़ें हैं और भाग जाने या विचारण से बचने या साक्ष्यों /गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई आशंका व्यक्त नहीं की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ 120बी के तहत अपराध करने के मामले में और अपनी पत्नी को मारने की साज़िश रचने के मामले में और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उपरोक्त शायद ही आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार हो सकता है।"

20.4.5. **राहुल गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य**[35] मामले में, इस न्यायालय ने इस बात पर और ज़ोर दिया कि एक बार जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र दायर हो जाने के बाद, उच्च न्यायालय को यह तय करने के लिए जांच के दौरान इकट्ठा किए गए साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है और क्या जमानत देना सही है। न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच करने के बाद जमानत के आदेश को रद्द कर दिया, आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया।

20.4.6. मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय सेक्शन 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध की गंभीरता और साजिश के आरोप के बावजूद, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए दोषी ठहराने वाले साक्ष्यों पर विचार करने में विफल रहा। सिर्फ आरोप-पत्र दाखिल करना, गवाहों की लंबी सूची का होना, या विचारण में देरी की संभावना, अपने आप में अपराध की गंभीरता को कम करने या अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मामले को नज़रअंदाज़ करने के वैध कारण नहीं हो सकते। जैसा कि इस न्यायालय ने बार-बार कहा है, ऐसे कारक हत्या जैसे जघन्य अपराधों में जमानत देने के लिए अकेले आधार नहीं हो सकते। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने को सही ठहराने के लिए अपनाया गया तर्क, स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है।

20.5. **<u>जमानत के बाद आरोपी का अच्छा व्यवहार, हालांकि जमानत जारी रखने के सवाल के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यह पिछले समय से एक अन्यथा अस्थिर आदेश को वैध नहीं ठहरा सकता।</u>**

20.5.1. यह तथ्य कि आरोपी 140 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में थे, या रिहाई के बाद अच्छा व्यवहार दिखाया, यह अपने आप में जमानत के आदेश को टिकाऊ नहीं बनाता है, अगर जमानत देते समय महत्वपूर्ण कारकों पर विचार नहीं किया गया हो।

20.5.2. **राज्य द्वारा सीबीआई बनाम अमरमणि त्रिपाठी**[36] मामले में, इस न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि "...सिर्फ यह तथ्य कि आरोपी ने कुछ समय जेल में बिताया है... अपने आप में आरोपी को जमानत पर रिहा करने का हकदार नहीं बनाता है... जब लगाए गए अपराध की गंभीरता गंभीर हो..."

20.5.3. **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने कहा:

"....उच्च न्यायालय ने आरोपी द्वारा पहले ही जेल में बिताई गई अवधि और **<u>निकट भविष्य में विचारण खत्म होने की संभावना न होने को आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार</u>**

<u>माना है, इस तथ्य के बावजूद कि आरोपी पर ऐसे अपराधों का आरोप है जिनके लिए आजीवन कारावास या मौत की सज़ा हो सकती है।</u> ऐसे मामलों में, हमारी राय में, सिर्फ यह तथ्य कि आरोपी ने जेल में कुछ समय बिताया है (इस मामले में तीन साल) अपने आप में आरोपी को जमानत पर रिहा करने का हकदार नहीं बनाता है, और न ही यह तथ्य कि विचारण निकट भविष्य में खत्म होने की संभावना नहीं है, या तो अकेले या जेल में बिताई गई अवधि के साथ मिलकर, आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्तहोगा, जब लगाए गए अपराध की गंभीरता गंभीर हो और आरोपी पर जमानत पर रहने के दौरान गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप हों।"

यह भी कहा गया कि

"जबकि यह अस्पष्ट आरोप कि आरोपी साक्ष्यों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, अगर आरोपी का चरित्र ऐसा है कि उसकी खुली मौजूदगी से गवाह डर जाएंगे या अगर यह दिखाने के लिए साक्ष्य हैं कि वह अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल न्याय को बिगाड़ने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा, तो जमानत से इनकार कर दिया जाएगा।"

20.5.4. **ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह @ लल्ला बाहू और अन्य**[37] में, न्यायालय ने दोहराया कि हिरासत की अवधि, हालांकि प्रासंगिक है, लेकिन अपराध की प्रकृति और आपराधिक पृष्ठभूमि सहित सभी परिस्थितियों के मुकाबले इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह माना गया कि:

"31. यह ध्यान दिया जाए कि एक ऐसा दौर आ गया है कि कुछ राज्यों में अगवा करने और अपहरण करने को बहादुरी माना जाने लगा है। समय के साथ कोई खास अपराध अपना रंग बदल लेता है। अपहरण के संदर्भ में अपराध की अवधारणा में सच में बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसने व्यवस्थित समाज की रीढ़ तोड़ दी है। लगभग हर दिन अपहरण से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों के बारे में पढ़ना लगभग घिनौना लगता है, खासकर उन लोगों के बारे में जो खुद को इस तरह के अपराध के विशेषज्ञ कहते हैं।

32. हम यह कहना चाहेंगे कि जब नागरिक शांतिपूर्ण जीवन जीने से डरते हैं और इस तरह के अपराध व्यवस्थित समाज की स्थापना में बाधा डालते हैं, तो न्यायालय का कर्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और बोझ भारी हो जाता है। आपराधिक विवरण का ठीक से विश्लेषण किया जाना चाहिए था। कहने की ज़रूरत नहीं है, शर्तें लगाना आरोपी को जमानत देने के आदेश के बाद होता है। यह सवाल पूछा

जाना चाहिए कि क्या आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार है या नहीं और उसके बाद ही शर्तें लगाने का सवाल उठेगा। हम एक पल के लिए भी यह इनकार नहीं करते कि हिरासत की अवधि एक प्रासंगिक कारक है, लेकिन साथ ही परिस्थितियों की समग्रता और आपराधिक विवरण पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन पर सामूहिक पुकार और इच्छा के पैमाने पर विचार किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक चिंता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उक्त मापदंड को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि इस मामले में सामाजिक चिंता को आरोपी की स्वतंत्रता पर लगी रोक हटाने से ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

33. वर्तमान संदर्भ में, हमारी राय में, सात महीने की हिरासत की अवधि महत्वहीन हो जाती है। हम दोहराते हैं कि जमानत देना उच्च न्यायालय का विवेकाधिकार है और यह न्यायालय ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप करने में हिचकिचाता है। लेकिन आरोपी के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए जो एक कारक भी है इस न्यायालय के फैसलों और किए गए अपराध की प्रकृति और पीड़ित को आठ दिनों तक कैद में रखने को ध्यान में रखते हुए, हम चुनौती दिए गए आदेश में दखल देने के लिए तैयार हैं।

34. हम यह नोट कर सकते हैं कि यह जमानत रद्द करने की अपील नहीं है क्योंकि बाद की परिस्थितियों के कारण रद्द करने की मांग नहीं की गई है। **यह मूल रूप से जमानत देने को चुनौती देने वाली अपील है, जिसमें उच्च न्यायालय प्रासंगिक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करने में विफल रहा है, जो आदेश को गलत बनाते हैं। तदनुसार, जमानत आदेश रद्द कर दिया गया और आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।**

20.5.5. हाल ही में, **अजवर बनाम वसीम[38]** में, इस न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा धारा 147, 148, 149, 302, 307, 352, और 504 भारतीय दंड संहिता के तहत दोहरे हत्याकांड से जुड़े एक हत्या के मामले में दी गई चार जमानत आदेशों को रद्द कर दिया, इस तथ्य के बावजूद कि आरोपी दो साल और आठ महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहा था। न्यायालय ने पाया कि जमानत महत्वपूर्ण तथ्यों पर उचित विचार किए बिना दी गई थी। तदनुसार, आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। निम्नलिखित अनुच्छेद ग्राफ प्रासंगिक है:

"33. इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-आरोपियों द्वारा किए गए इतने गंभीर अपराध के लिए हिरासत की अवधि को नजरअंदाज कर दिया है। यूपी राज्य के विद्वान वकील द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, जमानत पर रिहा होने से पहले, **आरोपी - वसीम**

लगभग दो साल चार महीने की अवधि के लिए हिरासत में था, आरोपी - नाजिम दो साल आठ महीने की अवधि के लिए, आरोपी - असलम लगभग दो साल नौ महीने की अवधि के लिए और आरोपी अबू बकर, दो साल दस महीने की अवधि के लिए। दूसरे शब्दों में, सभी आरोपी-प्रतिवादी दोहरे हत्याकांड जैसे गंभीर अपराध के लिए तीन साल से कम समय तक हिरासत में रहे हैं, जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया है।"

20.5.6. निष्कर्ष में, हालांकि जमानत के बाद अच्छा व्यवहार या जेल में बिताया गया समय जमानत जारी रखने के स्तर पर ज़रूरी बातें हो सकती हैं, लेकिन वे जमानत देने के आदेश में मौजूद बुनियादी त्रुटियों को ठीक नहीं कर सकते, जो अन्यथा गलत है, कानूनी रूप से

मान्य नहीं है, या अपराध की गंभीरता, पहली नज़र में शामिल होने, और गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना जैसे ज़रूरी बातों पर ठीक से विचार किए बिना पारित किया गया है। एक अमान्य जमानत आदेश सिर्फ समय बीतने या आरोपी के बाद के व्यवहार से वैध नहीं हो जाता। न्यायिक जांच इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि जमानत देने का विवेक, जमानत देते समय, समझदारी से और स्थापित सिद्धांतों के अनुसार इस्तेमाल किया गया था, न कि यांत्रिक तरीके से या तकनीकी आधार पर। इसलिए, प्रतिवादियों/आरोपियों को जमानत देने का उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करने लायक है।

21. अपीलकर्ता– राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने मुख्य रूप से अभियुक्त संख्या 2 को दी गई ज़मानत को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने उसकी हैसियत, उसके प्रभाव और जाँच में बाधा डालने में उसकी भूमिका पर ज़ोर दिया। यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त संख्या 2 ने सक्रिय रूप से व्यापक जनसंचार समर्थन जुटाया है और सार्वजनिक राय को अपने पक्ष में मोड़ा है, जिससे एक ऐसा माहौल बन गया है जो चल रही जाँच को प्रभावित कर सकता है और मुक़दमे की निष्पक्षता को कमज़ोर कर सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त संख्या 2 एक निष्क्रिय दर्शक नहीं था, बल्कि एक सक्रिय साज़िशकर्ता था जिसने अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, उच्च न्यायालय ज़मानत देते समय इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने में विफल रहा, जिससे विवादित आदेश की वैधता और औचित्य के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं।

22. अब हम उपरोक्त तर्कों की विस्तृत जाँच करते हैं।

(क) अपराध की प्रकृति और गंभीरता

22.1. कथित अपराध की गंभीरता और जघन्य प्रकृति, ज़मानत रद्द करने की याचिका का मूल्यांकन करते समय विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

22.1.1. **राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह**[39] में, इस न्यायालय ने कहा कि "अपराध की प्रकृति ज़मानत देने के लिए बुनियादी विचारों में से एक है – अपराध जितना जघन्य होगा, ज़मानत अस्वीकार होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, हालाँकि ऐसे मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता है।"

22.1.2. इसी तरह, **पंचानन मिश्रा बनाम दिगंबर मिश्रा**[40] में, न्यायालय ने देखा कि "ज़मानत रद्द करने का अंतर्निहित उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई की रक्षा करना और समाज को न्याय दिलाना है, ताकि जघन्य अपराधों में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।"

22.1.3. वर्तमान मामले में, आरोपी पर सह-आरोपी के साथ धारा 120बी, 302, 201 और 204 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो साज़िश, हत्या, साक्ष्यों को नष्ट करने और साक्ष्यों को गायब करने से संबंधित हैं। आरोप एक युवा व्यक्ति की क्रूर और हिरासत में हत्या का है, जिसे कथित तौर पर अभियुक्त संख्या 2 को आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए आरोपी द्वारा अपहरण किया गया, प्रताड़ित किया गया और पीट-पीटकर मार डाला गया। पीड़ित 26 साल का दिहाड़ी मजदूर था, और यह अपराध कथित तौर पर अभियुक्त संख्या 2, जो एक मशहूर हस्ती है, के जोड़ीदार अभियुक्त संख्या 1 की इज्जत बचाने के लिए किया गया था।

22.1.4. यह अचानक उकसावे या भावनात्मक आवेश का मामला नहीं है। साक्ष्य एक सोची-समझी और सुनियोजित अपराध की ओर इशारा करते हैं, जहाँ आरोपी ने न केवल कथित तौर पर कानून को अपने हाथ में लिया, बल्कि साक्ष्यों को व्यवस्थित तरीके से नष्ट करने में भी शामिल था, जिसमें शामिल हैं: सीसीटीवी फुटेज नष्ट करना, सह-आरोपियों को झूठा आत्मसमर्पण करने के लिए रिश्वत देना, और जाँच को पटरी से उतारने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रभाव का इस्तेमाल करना।

22.1.5. जैसा कि इस न्यायालय ने **जगन किशोर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[41] में चेतावनी दी थी, हिरासत में यातना और कथित अपराधी के गैर-न्यायिक निष्पादन से जुड़े मामलों में जमानत देना कानून के शासन में जनता के विश्वास को कम करता है। इस प्रकार, अपराध की गंभीरता ही जमानत

रद्द करने का औचित्य साबित करती है, खासकर जब अभियुक्त संख्या 2 को दी गई स्वतंत्रता से विचारण प्रक्रिया की निष्पक्षता को नुकसान पहुँचने की संभावना हो।

(ख) साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना

22.2. रिकॉर्ड से जाँच में हस्तक्षेप के ठोस कार्य सामने आते हैं, जिनमें शामिल हैं:

• सह-आरोपियों (अभियुक्त संख्या 10, अभियुक्त संख्या 14) द्वारा झूठे आत्मसमर्पण करवाने में अभियुक्त संख्या 2 की भूमिका;

• अपराध को छिपाने के लिए किए गए भुगतान (सह-आरोपियों के बयानों के अनुसार);

• पुलिस अधिकारियों के साथ संबंध जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट और पोस्टमार्टम प्रक्रियाओं में देरी की और उन्हें कमजोर किया;

• अभियुक्त संख्या 1 के आवास से सीसीटीवी साक्ष्यों को डिलीट करना;

• जमानत के बाद सार्वजनिक रूप से दिखने से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों पर लगातार प्रभाव बना हुआ है।

22.2.1. **पूरन बनाम रामबिलास**[42] में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि "जमानत रद्द करना तब स्वीकार्य है जब जमानत देने का आदेश गलत था, या यदि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ करता है या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करता है।"

22.2.2. **राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि "न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या न्याय प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर सकता है। अगर आरोपी विचारण प्रक्रिया में दखल दे सकता है तो उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।"

22.2.3. इसके अलावा, यह माना गया कि "आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना भी जमानत देने से इनकार करने के लिए काफी है।" **दीपक यादव**

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[43] मामले में, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका के कारण जमानत रद्द कर दी गई थी।

22.2.4. **पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[44] मामले में, न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि अगर आरोपी:

• साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है;

• गवाहों को प्रभावित करता है;

• दूसरों को झूठे बयान देने के लिए उकसाता है;

• या अगर न्याय में गड़बड़ी की वास्तविक आशंका है, तो जमानत रद्द की जा सकती है।

22.2.5. अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि अभियुक्त संख्या 2 सिर्फ़ ज़मानत के बाद स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, बल्कि वह जाँच को पटरी से उतारने की कोशिशों का षड्यन्त्रकर्ता है। ऐसी परिस्थितियों में, संभावनाओं की प्रधानता का परीक्षण लागू होता है (**संजय गांधी बनाम दिल्ली प्रशासन** मामले के अनुसार) और अभियोजन पक्ष को इस स्तर पर उचित संदेह से परे अपराध साबित करने की ज़रूरत नहीं है।

(ग) चिकित्सीय आधार पर गलतबयानी करके प्राप्त की गई ज़मानत

22.3. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पारित ज़मानत आदेश, मुख्य रूप से पहले प्रतिवादी/अभियुक्त संख्या 2 की कथित आपातकालीन चिकित्सीय स्थिति के आधार पर दिया गया था। हालाँकि, चिकित्सीय विवरण और आरोपी के बाद के आचरण को देखने से पता चलता है कि चिकित्सीय दलील गुमराह करने वाली, अस्पष्ट और बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई थी।

22.3.1. इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि चिकित्सीय आधार पर दी गई ज़मानत विश्वसनीय, विशिष्ट और तत्काल ज़रूरत पर आधारित होनी चाहिए, न कि सामान्य या भविष्य की आशंकाओं पर। [देखें: **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी** और **दिनेश एम.एन. बनाम गुजरात राज्य**, (उपरोक्त)]।

22.3.2. चिकित्सालय द्वारा दिनक 28.11.2024 को जारी की डिस्चार्ज सारांश में बताया गया है कि अभियुक्त संख्या 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप और पहले से ही दिल की समस्याओं का मरीज़ है, और उसे भविष्य में सीएबीजी शल्य चिकित्सा की ज़रूरत पड़ सकती है। हालाँकि, रिपोर्ट में यह संकेत नहीं

दिया गया है: कोई मौजूदा आपात स्थिति या तत्काल चिकित्सीय हस्तक्षेप की ज़रूरत; कोई जानलेवा स्थिति जिसके लिए तत्काल रिहाई की ज़रूरत हो; और जेल की चिकित्सीय प्रणाली की उसकी मौजूदा स्थिति को संभालने में कोई अक्षमता। इस प्रकार, ज़मानत देने के लिए कोई बाध्यकारी चिकित्सीय ज़रूरत नहीं है।

22.3.3. **पूरन बनाम रामबिलास** (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने कहा कि "अगर यह दिखाया जाता है कि किसी पक्ष ने गलतबयानी या धोखाधड़ी से, या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर ज़मानत प्राप्त की है, तो ऐसी ज़मानत केवल इसी आधार पर रद्द की जा सकती है"। इसी तरह, **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेंद्र नाथ सिन्हा**[45], यह देखा गया कि "तथ्यों को छिपाकर या न्यायालय को गुमराह करके प्राप्त की गई जमानत आदेश को अमान्य कर देती है, क्योंकि यह न्याय के हित को नुकसान पहुंचाती है"।

22.3.4. उच्च न्यायालय के सामने बनाई गई धारणा के विपरीत, अभियुक्त संख्या 2 ने कई सार्वजनिक जगहों पर उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें उच्च-श्रेणी के सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना शामिल है, वह अच्छी सेहत और चलने-फिरने की स्थिति में देखा गया, और रिहाई के बाद उसकी कोई शल्य चिकित्सा या गंभीर चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं हुई। इससे यह साबित होता है कि उसने जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, जो एक झूठे और गुमराह करने वाले आधार पर प्राप्त की गई थी।

22.3.5. **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि "चिकित्सीय आधार पर जमानत केवल असाधारण मामलों में दी जा सकती है जहां चिकित्सीय स्थिति गंभीर हो, हिरासत में इलाज संभव न हो, और जेल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न हों"। ऐसी आवश्यकता साबित करने का बोझ आरोपी पर होता है।

22.3.6. वर्तमान मामले में, अभियुक्त संख्या 2 यह साबित करने में विफल रहा कि जेल चिकित्सालय उसकी स्थिति को संभालने में असमर्थ था या न्यायिक हिरासत में पर्याप्त इलाज नहीं दिया जा सकता था। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने हिरासत में इलाज की तात्कालिकता, गंभीरता, या अपर्याप्तता पर कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज किए बिना जमानत दे दी। इसका परिणाम एक विकृत और कानूनी रूप से अस्थिर जमानत आदेश है, जिसे **पूरन और समरेंद्र नाथ भट्टाचार्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[46] में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार रद्द किया जा सकता है।

<u>(घ) उच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार न करना</u>

22.4. एक आदेश जो महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ करता है या गलत आधार पर आगे बढ़ता है, वह विकृत होता है, और ऐसी विकृति जमानत रद्द करने या उसे रद्द करने का एक वैध आधार बनती है।

22.4.1. **महिपाल बनाम राजेश कुमार** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने कहा था कि "जहां जमानत देने का आदेश अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, या महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है, तो वह विकृत हो जाता है और उसे रद्द किया जा सकता है।" इसी तरह, **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी** (उपरोक्त) न्यायालय ने माना कि "जमानत के आदेश मामले के तथ्यों और अपराध की गंभीरता पर ध्यान से और समझदारी से विचार करने के बाद ही दिए जाने चाहिए। संबंधित सामग्री पर विचार न करने से आदेश को चुनौती दी जा सकती है।

22.4.2. इस मामले में, उच्च न्यायालय आरोपों की प्रकृति का ठीक से मूल्यांकन करने में विफल रहा, जिसमें सोची-समझी हत्या और साजिश शामिल थी, जो धारा 302 भारतीय दंड संहिता के साथ धारा 120बी भारतीय दंड संहिता के तहत आती है; परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, कॉल विवरण और फोरेंसिक विवरण शामिल है जो साक्ष्यों को नष्ट करने की जानबूझकर की गई कोशिश दिखाती है (जैसे, खून से सने कपड़े और गाड़ी को ठिकाने लगाना); और अभियुक्त संख्या 2 की दोषी भूमिका, जो घटना से पहले और बाद में अभियुक्त संख्या 1 और अन्य सह-आरोपियों के लगातार संपर्क में था, और जिसने साजिश और साक्ष्य छिपाने में मदद की। दूसरी ओर, इसने बस यह दर्ज किया कि अभियुक्त संख्या 2 की "कोई सीधी भूमिका नहीं" थी और "कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं" था, बिना विवरण पर मौजूद दोषी सामग्री पर चर्चा या विश्लेषण किए। यह दिमाग का इस्तेमाल न करने के बराबर है, और आदेश को कानून की नज़र में अस्थिर बनाता है।

22.4.3. **नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने जमानत देने के फैसले को पलटते हुए कहा कि "जहां उच्च न्यायालय महत्वपूर्ण परिस्थितियों और ठोस तथ्यों को नज़रअंदाज़ करता है, तो आदेश का बचाव नहीं किया जा सकता"।

22.4.4. मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय यह दर्ज किया कि अभियुक्त संख्या 2 अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था, लेकिन साथ ही, यह भी स्वीकार किया कि वह महत्वपूर्ण समय पर अन्य आरोपियों के साथ दूरभाष पर संपर्क में था। इसी तरह, उसने यह भी नोट किया कि कोई मज़बूत मकसद नहीं था, जबकि मृतक के साथ बाद की दुश्मनी और पहले की दुश्मनी को भी स्वीकार किया।

ये विरोधाभासी निष्कर्ष जमानत के आधार को खत्म कर देते हैं और संकेत देते हैं कि आदेश बिना किसी सुसंगत या कानूनी रूप से सुसंगत तर्क के पारित किया गया था।

22.4.5. आजीवन कारावास या मौत की सज़ा वाले अपराधों में, जमानत न्यायालय को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। **ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गंभीर अपराधों में, "अपराध की गंभीरता और समाज पर उसके प्रभाव को न्यायालय को गंभीरता से लेना चाहिए, और ऐसे मामलों पर अधिक सावधानी और विवेक के साथ विचार किया जाना चाहिए"। हालांकि, मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय का आदेश इस तरह की किसी भी उच्च जांच या सतर्क दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है, इसके बावजूद कि आरोप गंभीर है और मामले का व्यापक सामाजिक प्रभाव है।

23. भारत का संविधान अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है, और यह अनिवार्य करता है कि कोई भी व्यक्ति - चाहे वह कितना भी अमीर, प्रभावशाली या प्रसिद्ध क्यों न हो - कानून की सख्ती से छूट का दावा नहीं कर सकता। मशहूर हस्ती का दर्जा किसी आरोपी को कानून से ऊपर नहीं उठाता है, न ही उसे जमानत देने जैसे मामलों में विशेष व्यवहार का हकदार बनाता है।

23.1. **महाराष्ट्र राज्य बनाम धनेंद्र श्रीराम भुरले**[47] में, यह देखा गया कि "सार्वजनिक विश्वास से जुड़े गंभीर अपराधों में जमानत देने के मामले को बहुत सावधानी से संभाला जाना चाहिए, खासकर जहां आरोपी प्रभावशाली हो"।

23.2. **प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता**[48] में, इस न्यायालय ने कहा कि "समाज में आरोपी की स्थिति और रुतबा मायने रखता है। अगर आरोपी इतना प्रभावशाली है कि उसकी खुली मौजूदगी से गवाहों को डराया जा सकता है या न्याय में बाधा डाली जा सकती है, तो जमानत से इनकार किया जा सकता है या उसे रद्द किया जा सकता है।"

23.3. **वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई**[49] में, इस न्यायालय ने चेतावनी दी कि "समाज में आरोपी की स्थिति या रुतबा, अगर जांच या विचारण को प्रभावित करने की संभावना है, तो जमानत खारिज करने के लिए यह एक वैध कारण है"।

23.4. इसी तरह, **राणा कपूर बनाम प्रवर्तन निदेशालय**[50] में, इस न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि "प्रभावशाली लोग साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। जमानत के मामलों में इस कारक पर ध्यान से विचार किया जाना चाहिए"।

23.5. लोकप्रियता माफी की ढाल नहीं हो सकती। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा, प्रभाव, संसाधन और सामाजिक रुतबा जमानत देने का आधार नहीं बन सकते, जहां जांच या विचारण को नुकसान पहुंचने का वास्तविक खतरा हो।

23.6. मौजूदा मामले में, अभियुक्त संख्या 2 के रुतबे को एक नरम कारक मानकर, उच्च न्यायालय ने अपने विवेक का इस्तेमाल करने में एक स्पष्ट गलती की, जिससे जमानत रद्द करना ज़रूरी हो गया। जैसा कि पहले दिखाया गया है, अभियुक्त संख्या 2 कोई आम विचाराधीन कैदी नहीं है। वह मशहूर हस्ती का दर्जा, भारी जनसमर्थन, राजनीतिक दबदबा और वित्तीय ताकत रखता है। जेल के अंदर उसका आचरण - जिसमें विशेष व्यक्ति को दी जानी वाली सुविधा के दर्ज किए गए मामले, जेल के नियमों का उल्लंघन, और सुविधाओं के दुरुपयोग के लिए दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल हैं- यह दर्शाता है कि वह हिरासत में रहते हुए भी व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता रखता है। अगर कोई व्यक्ति जेल व्यवस्था को ही बिगाड़ सकता है, तो साक्ष्यों से छेड़छाड़, गवाहों को धमकाने या प्रभावित करने, और न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने का खतरा वास्तविक और आसन्न है।

23.7. इसके अलावा, जमानत पर होने के बावजूद, अभियुक्त संख्या 2 का तुरंत सामाजिक कार्यक्रमों में लौटना, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ मंच साझा करना, और पुलिस गवाहों पर लगातार प्रभाव बनाए रखना, यह साबित करता है कि उसकी स्वतंत्रता कार्यवाही की निष्पक्षता के लिए खतरा है।

23.8. गौरतलब है कि मशहूर हस्ती सामाजिक अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में काम करते हैं- उनकी जवाबदेही ज़्यादा होती है, कम नहीं। वे अपनी प्रसिद्धि और सार्वजनिक उपस्थिति के कारण सार्वजनिक व्यवहार और सामाजिक मूल्यों पर काफी प्रभाव डालते हैं। साजिश और हत्या जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद ऐसे लोगों को नरमी बरतना समाज को गलत संदेश भेजता है और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है।

23.9. इसलिए, अभियुक्त संख्या 2 का पिछला आचरण, उसका प्रभाव, जेल में उसका गलत व्यवहार, और उसके खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता उसे ज़मानत के लिए अयोग्य बनाती है, और उसे ज़मानत देने का आदेश बिना सोचे-समझे, गलत और इसलिए, कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

24. कुल मिलाकर विश्लेषण करने पर, यह साफ है कि उच्च न्यायालय का आदेश गंभीर कानूनी त्रुटियों से ग्रस्त है। यह आदेश धारा 302, 120बी, और 34 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपों वाले मामले में जमानत देने के लिए कोई विशेष या ठोस कारण दर्ज करने में विफल रहा है। इसके बजाय, यह विवेक का एक यांत्रिक प्रयोग दिखाता है, जिसमें कानूनी रूप से प्रासंगिक तथ्यों की महत्वपूर्ण चूक है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने मुकदमे से पहले के चरण में गवाहों के बयानों की व्यापक जांच की, जिसमें कथित विरोधाभासों और देरी को उजागर किया गया - ऐसे मुद्दे जो स्वाभाविक रूप से विचारण न्यायालय द्वारा जिरह के माध्यम से मूल्यांकन करने के मामले हैं। गवाहों की विश्वसनीयता और भरोसेमंदता का मूल्यांकन करने के लिए केवल विचारण न्यायालय ही उचित मंच है। ऐसे गंभीर मामले में, अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की भूमिका, और मुकदमे में हस्तक्षेप के ठोस जोखिम पर पर्याप्त विचार किए बिना जमानत देना, विवेक का एक विकृत और पूरी तरह से अनुचित प्रयोग है। गवाहों को डराने-धमकाने के ठोस आरोप, साथ ही ठोस फोरेंसिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जमानत रद्द करने की आवश्यकता को और मजबूत करते हैं। नतीजतन, विवादित आदेश के तहत दी गई स्वतंत्रता न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के लिए एक वास्तविक और आसन्न खतरा पैदा करती है और विचारण प्रक्रिया को पटरी से उतारने का जोखिम है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय संतुष्ट है कि वर्तमान मामला धारा 439(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग की मांग करता है।

25. कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में, कोई भी व्यक्ति स्थिति या सामाजिक पूंजी के आधार पर कानूनी जवाबदेही से मुक्त नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और मनमानी पर रोक लगाता है। यह अनिवार्य करता है कि सभी व्यक्ति - उनकी लोकप्रियता, शक्ति, या विशेषाधिकार की परवाह किए बिना - समान रूप से कानून के अधीन हैं।

26. उपरोक्त को देखते हुए, ये सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.12.2024 का आदेश रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों/आरोपी व्यक्तियों को दी गई जमानत इसके द्वारा रद्द की जाती है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आरोपी को तुरंत हिरासत में लें। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, विचारण तेजी से चलाया जाएगा, और कानून के अनुसार,

योग्यता के आधार पर निर्णय सुनाया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां सख्ती से जमानत के मुद्दे तक सीमित हैं और योग्यता के आधार पर विचारण को प्रभावित नहीं करेंगी।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

<u>आदेश</u>

जे.बी. परदीवाला, न्यायमूर्ति

1. मेरे सम्मानित भाई न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने अभी-अभी एक बहुत ही विद्वतापूर्ण निर्णय सुनाया है। मैं एक वाक्य में बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे सम्मानित भाई द्वारा लिखा गया निर्णय अकथनीय है। यह निर्णय एक बहुत मजबूत संदेश देता है कि आरोपी कोई भी हो, आरोपी कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है। इस आदेश में एक बहुत मजबूत संदेश है कि न्याय व्यवस्था को किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून का शासन बना रहे। कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है और कोई भी आदमी इसके नीचे नहीं है; और न ही हम किसी आदमी से इसकी आज्ञा मानने के लिए उसकी अनुमति मांगते हैं। कानून का पालन एक अधिकार के रूप में मांगा जाता है; एहसान के तौर पर नहीं। समय की मांग है कि हर समय कानून का शासन बनाए रखा जाए।

2. जिस दिन हमें पता चलेगा कि आरोपी व्यक्तियों को जेल परिसर के अंदर कोई विशेष या पाँच-सितारा सुविधाएं दी जा रही है, तो इस प्रक्रिया में पहला कदम जेल अधीक्षक को निलंबित करना होगा, जिसमें ऐसे दुराचार में शामिल अन्य सभी अधिकारी भी शामिल होंगे।

3. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति सभी उच्च न्यायालय और देश भर के सभी जेल अधीक्षकों को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से भेजी जाए।

मामले का परिणाम : अपीलें स्वीकार की गयीं।

शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्या पांडे द्वारा तैयार की गई।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक (मदन मोहन प्रिय) द्वारा किया गया है।